CMYK

RNI.No. — GUJHIN/2012/45192

सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर। मिश्रा

श्री 1008 महामंडलेश्वर
श्री स्वामी रामानंद दासजी महाराज
श्री रामानंद दास अन्नक्षेत्र सेवा ट्रस्ट, तपोवन आश्रम

स्व. पं. पू.1008 श्री रामानन्द जी
तपोवन मंदिर, मोरा गांव, सूरत

वर्ष-9 अंक: 323 ता. 04 जून 2021, शुक्रवार कार्यालय:114, न्यु प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, उधना सूरत (गुजरात) मो। 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com /Suratbhumi.com /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi

नीति आयोग ने जारी की एसडीजी 2020-21 रिपोर्ट, केरल फिर अव्वल और बिहार फिर फिसड्डी

नई दिल्ली। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डेशबोर्ड 2020-21 के तीसरे संस्करण को जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केरल एक बार फिर से इसमें नंबर वन के स्थान पर काबिज है। वहीं बिहार पहले की ही तरह इस सूची में सबसे नीचे है। इसका सीधा सा अर्थ है कि बिहार की प्रोग्रेस रिपोर्ट और उसका प्रदर्शन बेहद खराब है। ये रिपोर्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आर्थिक और पर्यावरण का आंकलन करते हुए तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में केरल को 75 अंक हासिल हुए हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को एक समान 74 अंक हासिल हुए हैं और ये दूसरे नंबर पर काबिज हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें केवल बिहार ही शामिल नहीं है बल्कि असम और झारखंड भी है। आपको बता दें कि वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट में 13 गोल, 39 टार्गेट, 62 इंडीकेटर्स शामिल थे जबकि 2019-20 में 17 गोल, 54 टार्गेट, और 100 इंडीकेटर्स को इसका मापक बनाया गया था। इसी तरह से मौजूदा रिपोर्ट में 17 गोल, 70 टार्गेट और 115 इंडीकेटर्स को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तरक्की का पैमाना बनाया गया था। इसी तरह 2030 के लिए 17 गोल और 169 संबंधित लक्ष्य का पैमाना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखा गया है। इसकी शुरुआत पहली बार 2018 में की गई थी और अब ये तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन लक्ष?यों की प्राप्ति के आधार पर रैंकिंग भी दी गई है। देश में इन सतत विकास के लक्ष्यों को पाने की दिशा में ये एक प्राइमरी टूल है। इसके जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपसी प्रतियोगिता बढ़ती है और आगे आने की चाह में देश विकास की राह पर आगे बढ़ता है। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नजर नहीं आता।

वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी:

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा; कहा- पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बना रही कंपनी; यह कानून के खिलाफ

नई दिल्ली। वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा पेश कर दिया। केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा कि वॉट्सऐप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। वह अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ है। केंद्र ने मांग की है कि कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जाने वाले नोटिफिकेशन को लेकर अंतरिम निर्देश दे।

नई पॉलिसी यूजर्स पर थोपी जा रही- केंद्र

वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में 15 मई से लागू हो गई है। नई पॉलिसी पर सरकार ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन अभी तक

पॉलिसी पर कटघरे में वॉट्सऐप

वॉट्सऐप नई प्राइवेसी पॉलिटी को लेकर अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के खिलाफ है। इस पर अंतरिम निर्देश जारी किया जाए।

- दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद सरकार ने कोर्ट में कहा है कि वॉट्सऐप अपनी नई पॉलिसी यूजर्स पर थोप रहा है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रहा है। वह बड़ी होशियारी से डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा है।

केंद्र सरकार जता चुकी है आपत्ति

वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार आपत्ति जता चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वॉट्सऐप के ष्टश्वह्र विल कैथकार्ट को सख्त पत्र लिखकर कहा था कि वैश्विक स्तर पर भारत में वॉट्सऐप का सबसे ज्यादा यूजर बेस और सबसे बड़ा बाजार है। वॉट्सऐप की सेवा शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई हैं। मंत्रालय ने पॉलिसी में किए गए बदलावों को वापस लेने के लिए कहा था।

क्या है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी?

वह अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ है।

वॉट्सऐप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था।

350 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ, भारत विश्व में पांचवें स्थान पर

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच भारत के अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र से अच्छी खबर आई है। भारत में निजी अंतरिक्ष फर्मों की संख्या 350 से अधिक हो गई है। जो इस क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे जापान, चीन और रूस से अधिक है, यह संख्या भारत को विश्व में पांचवें स्थान पर रखती है। वैश्विक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में विश्लेषण की गई 10,000-विषम फर्मों में से, जो 2025 तक अंतरिक्ष तकनीक अर्थव्यवस्था को 500 ट्रिलियन डॉलर के होने का अनुमान लगाती है, 5,500 से अधिक अमेरिका में हैं, इसके बाद यूके, कनाडा और जर्मनी हैं। रिपोर्ट में चीन, फ्रांस और स्पेन में क्रमशः 288, 269 और 206 की तुलना में भारत में 368 फर्मों को सूचीबद्ध किया गया है। जापान और रूस में क्रमशः 184 और 56 फर्म हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा कि 'अंतरिक्ष उद्योग से जुड़ी बड़ी और छोटी दोनों तरह की फर्मों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 2020 के अंत की तुलना में इन-स्पेस के प्रस्तावों की संख्या में भी लगभग 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। स्पेसटेक एनालिटिक्स की रिपोर्ट स्पेसटेक इंडस्ट्री 2021/क्यू2 लैंडस्केप ओवरव्यू के अनुसार, वैश्विक स्तर पर ज्यादातर कंपनियां (2,820) नेविगेशन और मैपिंग में हैं, इसके बाद 1,000 विनिर्माण फर्म, 718 स्पेस कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग (211), एरियल इमेजिंग (152), अंतरिक्ष यान विकास (80), अंतरिक्ष यात्रा (58), और अंतरिक्ष चिकित्सा (48) के क्षेत्र में काम रही हैं। वैलेस मेरिनरिस इंटरनेशनल, जो रूस में अपने भागीदारों के माध्यम से वैश्विक अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने में मदद करता है, के सीईओ जयकुमार वेंकटेशन, कहते हैं कि इसरो जिस मॉडल का अनुसरण कर रहा है उसे अमेरिका में बदलना चाहिए। यदि हम उद्योग को विकसित करना चाहते हैं तो हमारे पास विक्रेता-ग्राहक संबंध मॉडल नहीं हो सकता है, यह साझेदारी आधारित होना चाहिए। रिपोर्ट, जो अंतरिक्ष तकनीक अर्थव्यवस्था को मौजूदा 380 बिलियन डॉलर से 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर के छूने का अनुमान लगाती है, ने उक्त तिमाही के दौरान ऐसी कंपनियों में किए गए निवेश का भी विश्लेषण किया है। इसने दुनिया भर में 10,000 फर्मों, 5,000 निवेशकों, 150 आरएंडडी हब और संघों के साथ-साथ 130 सरकारी संगठनों की समीक्षा की है।

टीके से नुकसान पर भी कोई न कर पाए केस

कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टिट्यूट ने सरकार से मांगी सुरक्षा

नई दिल्ली। भारत में ऐस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने टीके जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावों से कानूनी सुरक्षा मांगी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि यह खबर ऐसे समय में आई है जब इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत सरकार फाइज़र और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों को इस तरह का संरक्षण दे सकती है।

दरअसल, भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कई विदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ करार किया है। हालांकि, एक कानूनी मसले को लेकर पेच फंसा हुआ सा लग रहा था। अमेरिकी कंपनी फाइज़र और मॉडर्ना ने भारत सरकार से मांग की थी कि वह उनकी कोविड-19 वैक्सीन के

अगर विदेशी कंपनियों को किसी क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे से छूट मिल रही है तो फिर सिर्फ सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही क्यों बल्कि वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को इससे छूट मिलनी चाहिए।

इस्तेमाल से जुड़े किसी भी दावे से उसे कानूनी सुरक्षा दे। खबरों के मुताबिक, भारत सरकार भी इसपर तैयार हो गई थी। अब सीरम इंस्टिट्यूट ने भी अपने टीके को लेकर इसी तरह की सुरक्षा की मांग की है।

समाचार एजेंसी एएनआई को सूत्रों ने बताया, अगर विदेशी कंपनियों को किसी क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे से छूट मिल रही है तो फिर सिर्फ सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ही क्यों बल्कि वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को इससे छूट मिलनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले भारत की दवा नियामक संस्था यानी डीजीसीआई ने फाइज़र और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए इनके अलग से लोकल ट्रायल करवाने की शर्तों को हटा दिया था। नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी टीके को बड़े देशों की दवा नियामक संस्था या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी होगी, उन्हें भारत में अलग से ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ेगा।

महामारी में 9346 बच्चे बेसहारा, सबसे ज्यादा 2110 यूपी में प्रभावित, बिहार-मध्यप्रदेश भी बेहाल

नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर का असर पूरे देश पर पड़ा है। महामारी की मार का सबसे ज्यादा असर मासूम बच्चों पर पड़ा है। आंकड़ों पर गौर करें तो पूरे देश में अब तक 9346 बच्चे अनाथ या बेसहारा हो चुके हैं। इनमें अधिकतर ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया, जबकि काफी बच्चों के सिर से एक अभिभावक का साया उठ गया। यह जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। जस्टिस एलएन राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष पेश महाराष्ट्र सरकार ने आंकड़े पेश किए। इनमें बताया गया कि 30 मई तक राज्य के विभिन्न इलाकों में 4,451 बच्चों ने अपने माता-पिता में से एक को खो दिया है। वहीं, 141 बच्चे ऐसे हैं, जिनके माता-पिता दोनों की मौत हो गई।

बेसहारा बच्चे यूपी में सबसे ज्यादा

एनसीपीसीआर की वकील स्वरूपमा चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2110 बच्चे बेसहारा हो गए, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा है।

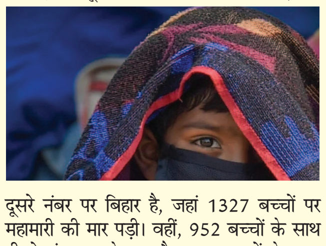

दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां 1327 बच्चों पर महामारी की मार पड़ी। वहीं, 952 बच्चों के साथ तीसरे नंबर पर केरल और 712 बच्चों के साथ चौथे नंबर पर मध्यप्रदेश है। ये बच्चे कोरोना महामारी के कारण अनाथ हो गए या फिर माता-पिता में से किसी एक को खो दिया।

सुप्रीम कोर्ट-पत्रकार विनोद दुआ को राहत, राजद्रोह के आरोप में दर्ज कराई गई प्राथमिकी रद्द

नई दिल्ली। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को खारिज कर दिया है। बता दें कि विनोद दुआ की ओर से एक यूट्यूब प्रोग्राम में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा के एक स्थानीय नेता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने अपने आदेश में विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह (आईपीसी की धारा-124ए) सहित अन्य अपराधों के तहत दर्ज मुकदमे को निरस्त

विनोद दुआ की ओर से एक यूट्यूब प्रोग्राम में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा के एक स्थानीय नेता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने अपने आदेश में विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह (आईपीसी की धारा-124ए) सहित अन्य अपराधों के तहत दर्ज मुकदमे को निरस्त कर दिया है।

कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पत्रकार, केदारनाथ सिंह फैसले के तहत संरक्षित हैं। इस फैसले में राजद्रोह कानून को सही ठहराया गया था लेकिन इसमें इस कानून का दायरा तय किया गया था। हालांकि कोर्ट ने पत्रकारों पर लगे आरोपों को सत्यापित करने के लिए समिति के गठन की विनोद दुआ की मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ की ओर से दायर की गई दूसरी याचिका को खारिज कर दिया। इसमें एफआईआर दर्ज करने से पहले पत्रकारों के खिलाफ आरोपों को सत्यापित करने के लिए एक समिति बनाने की मांग की गई थी और कहा गया था कि 10 साल से अधिक के अनुभव वाले पत्रकार के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए जब तक कि समिति द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती। कोर्ट ने कहा कि यह मसला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। विनोद दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले भाजपा नेता श्याम का कहना था कि दुआ ने अपने यू ट्यूब कार्यक्रम 'द विनोद दुआ शो' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने की खातिर 'मौत और आतंकी हमलों' का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। श्याम का कहना था कि इस तरह के बयान से शांति और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हो सकता था।

मॉडल किरायेदारी कानून को सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल किरायेदारी कानून (मॉडल टेनेंसी एक्ट) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत संपत्ति को किराये पर देने से पहले मकान मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता अनिवार्य होगा। इस कानून को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां लागू कर सकेंगे। यह कानून किरायेदार और मकान मलिक दोनों को समान अधिकार देता है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में खाली पड़ीं एक करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी को किराये पर चढ़ाया जा सकेगा। इस नए मॉडल कानून का खाका सबसे पहले 2019 में जारी किया गया था। मंत्रिमंडल के बुधवार के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस नए कानून से पुरानी व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। पगड़ी व्यवस्था पर भी असर नहीं पड़ेगा। पहले से जो लोग किराए पर रह रहे हैं या जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किराये पर चढ़ा रखी है उन पर भी यह लागू नहीं होगा। यह मॉडल कानून है और यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वह इसे अपने यहां लागू करें या ना करें।

ऐसे समझें नये कानून को-

-कोई भी व्यक्ति बिना लिखित समझौते के अपनी प्रॉपर्टी को न तो किराये पर दे सकेगा और न ही ले सकेगा।

-इसमें किराये की राशि को लेकर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। मकान मालिकों में प्रॉपर्टी को किराये पर देने के लिए ज्यादा भरोसा पैदा होगा।

-जो भी लिखित समझौता होगा उसे रेंट अथॉरिटी के सामने जमा करना होगा। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से प्रभावी होगा।

-किरायेदार और मकान मालिक के बीच विवाद होने पर तय समयावधि (60 दिन) में निपटारे की भी व्यवस्था।

-किरायेदार को प्रॉपर्टी को किसी और को किराये पर देने से पूर्व मकान मालिक की अनुमति लेनी जरूरी होगी। अनुमति के बगैर वह प्रॉपर्टी में निर्माण संबंधी बदलाव नहीं कर सकेगा।

-विवाद की स्थिति में भी किरायेदार को किराया देना होगा। इस दौरान उसे प्रॉपर्टी खाली नहीं करनी होगी।

-किसी बड़ी घटना की स्थिति में भी मकान मालिक को किरायेदार को एक महीने

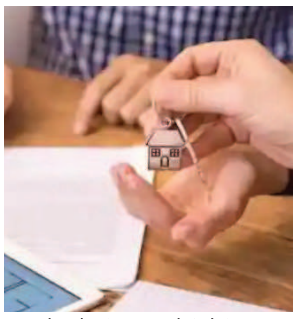

तक बने रहने की अनुमति देनी होगी।

दो महीने की सिक्योरिटी जमा करनी होगी-एक्ट में आवासीय प्रॉपर्टी के लिए दो महीने की धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट), जबकि वाणिज्यिक प्रॉपर्टी के लिए छह महीने की धरोहर राशि जमा करने की भी व्यवस्था की गई है। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट में राज्यों को संबंधित अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार किराये की प्रॉपर्टी को लेकर किसी विवाद के जल्द समाधान के लिए रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल भी बना बनाएंगे। इनको डिप्टी कलेक्टर या उसके समकक्ष रैंक के अधिकारी हेड करेंगे।

ये भी फायदे

नया कानून देश में किराये से संबंधित पूरे कानूनी ढांचे में बड़ा बदलाव करेगा जिससे देश में किराये पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी में तेजी आएगी। इससे किराये की प्रॉपर्टी का मार्केट भी बढ़ेगा। इसका उद्देश्य सभी आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। इससे आवास न मिलने की स्थिति में बनने वाली झुग्गी झोपड़ियों की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। इस कानून का एक फायदा यह भी होगा कि प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पूरी तरह कानूनी दायरे में होगी। इससे प्रॉपर्टी पर कब्जा करने या मकान मालिक द्वारा किरायेदार की प्रताड़ना की घटनाएं भी नहीं होंगी।

लोगों की आय बढ़ेगी- हरदीप पुरी

हरदीप पुरी ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में एक करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी खाली पड़ी थीं। अब 10 साल के भीतर इसकी संख्या डेढ़ करोड़ से ऊपर हो सकती है। इस प्रॉपर्टी के किराये पर जाने से बहुत बड़ी समस्या हल होगी और लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।

सार समाचार

भोपाल सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, गुजरात की तेल कंपनी के 678 करोड़ का घोटाला किया उजाकर

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की सीबीआई टीम ने 679 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी के मामले में की बड़ी कार्यवाही। बताया जा रहा है कि उन्होंने गुजरात की तेल कंपनी के 6 ठिकानों पर दबिश दी है। कार्रवाई गुजरात के अहमदाबाद और मेहसाणा में की जा रहीं है। सीबीआई टीम ऑयल कंपनी और उसके डायरेक्टरों के आवास पर भी तलाशी की। बता दें कि सीबीआई ने इस कार्यवाही को बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुई 678 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में की। इस मामले में मेहसाणा स्थित तेल कंपनी विमल ऑयल और उसके निर्देशकों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज करवाई है। दरअसल मामले में आरोपी बताए जा रहें मुकेश कुमार नारणभाई पटेल, दितिन नारायणभाई पटेल, जयेशभाई चंदूभाई पटेल, और मोना जिग्नेशभाई आचार्य ने बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित बैंकों से लगभग 810 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। जिसका उपयोग साल 2014 से 2017 के बीच दूसरे कार्यों में किया गया। जिससे बैंक को 678 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार

नयी दिल्ली। कोविड मरीजों के परिवारों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पर कथित तौर पर ठगी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक किशोर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि दिल्ली के एक निवासी की शिकायत पर बिहार के नालंदा और शेखोपुर सराय में छापे मारने के बाद बालेंदर चौधरी, कामेश्वर प्रसाद और गोपाल को गिरफ्तार किया गया जबकि किशोर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक विशेष कार्य सौंपा गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मामला तब प्रकाश में आया जब दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 की एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे पंकज नाम के एक व्यक्ति ने ठगा था। उसने शिकायतकर्ता के दादा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था जो कोविड से ग्रस्त थे। उन्होंने बताया कि महिला ने सोशल मीडिया पर मिले एक नंबर के जरिए दो ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए ऑर्डर दिया और ऑनलाइन 15,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया। पुलिस ने बताया कि पैसा भेजे जाने के बाद शिकायतकर्ता को सिलेंडर नहीं मिले और आरोपी ने उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अतुल कुमार ठाकुर ने कहा, ऽहमने संयुक्त टीम गठित की जिसने तकनीकी जांच की और संदिग्धों के विवरण प्राप्त किए जिनके मोबाइल नंबर और बैंक खाते नालंदा में सक्रिय मिले।ऽ

मुंबई को चार जून को कोविशील्ड की 87,000 खुराकें मिलने की संभावना: महापौर

मुंबई। बीएमसी की महापौर किशोरी पेडनेकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुंबई को शुक्रवार को कोविशील्ड की 87,000 खुराकें मिलने की संभावना है और इसके अगले दिन टीकाकरण अभियान बहाल हो जाएगा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने पूर्व में बताया था कि टीके की पर्याप्त खुराकें उपलब्ध नहीं रहने के कारण मुंबई में बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रों पर बृहस्पतिवार को टीकाकरण अभियान रोक दिया गया गया। मुंबई में कोविड-19 टीकाकरण के लिए कुल 342 केंद्र में 243 का संचालन बीएमसी और 20 का संचालन राज्य सरकार कर रही है

टीकाकरण को लेकर केंद्र पर नवाब मलिक का हमला, कहा- हर दिन नया फैसला होता है

नयी दिल्ली। देश में कोरोना महामारी लगातार जारी है। इन सबके बीच टीकाकरण को लेकर कई राज्यों और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इन सबके बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक नवाब मलिक ने कहा कि टीकाकरण को लेकर केंद्र की नीति स्पष्ट नहीं है। हर दिन नया फैसला होता है। पहले फाइजर को कहा गया कि लीगल जिम्मेदारी उनकी होगी। अब सुना जा रहा है कि उन्हें अनुमति दी जा रही है। 35,000 करोड़ का बजट था तो आपने खरीदा क्यों नहीं? राज्यों को जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है?

डीएमए की 'कोरोनिल किट' के खिलाफ दायर वाद में बाबा रामदेव को समन जारी

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु रामदेव को, पतंजलि की 'कोरोनिल किट' के कोविड-19 के उपचार के लिए कारगर होने की झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) की ओर से दायर वाद पर योग गुरू को बृहस्पतिवार को समन जारी किया। उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से योग गुरु रामदेव के वकील से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख, 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान नही देने और मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लियेकहें। चिकित्सकों की ओर से डीएमए ने कहा कि रामदेव का बयान प्रभावित करता है क्योंकि वह दवा कोरोना वायरस का इलाज नहीं करती और यह भ्रामक करने वाला बयान है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड-19 की जंग सफलतापूर्वक लड़ी: अमित शाह

अहमदाबाद। (एजेंसी)।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ जंग सफलतापूर्वक लड़ी और 135 करोड़ नागरिकों की मदद से बीमारी का ग्राफ नीचे लाने में कामयाब रहे। शाह ने कहा, ÷अब, मामले घट रहे हैं, मरीजों की संख्या कम हो रही है। ऑक्सीजन की जरूरत 10,000 मीट्रिक टन से घटकर 3,500 मीट्रिक टन पर आ गई है। यह दिखाता है कि कोविड-19 का वक्र नीचे आ रहा है।÷ उन्होंने यह भी कहा कि भारत के टीकाकरण अभियान की गति विश्व में सबसे तेज है और यह भविष्य में और गति पकड़ेगा ताकि कम से कम समय में अधिकतम लोगों को कवर किया जा सके जैसा कि प्रधानमंत्री ने परिकल्पना की है। शाह गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सरकारी अस्पतालों में लगाए गए नौ चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बोल रहे थे। ये ऑक्सीजन संयंत्र गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) वल्लभ यूथ ऑर्गनाइजेशन द्वारा तिलकवाड़ा, सागबारा, अहमदाबाद (सोला सिविल), अहमदाबाद जिले के दसकरोई, कलावाड़, कापड़वंज, भानवाड़, मेहसाना और पोरबंदर के अस्पतालों में लगाए गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर से इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

शाह ने कहा कि वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने और मामलों में कमी लाने में सरकार को सफलता सामूहिक प्रयासों से मिली है। उन्होंने कहा, ÷जैसा कि आपने मीडिया की खबरों में देखा होगा कि बहुत विकसित देशों को भी वैश्विक महामारी से निपटने में संघर्ष करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ, हमने यह लड़ाई धैर्य एवं योजना के साथ लड़ी है।'' शाह ने कहा कि अन्य देशों में केवल सरकारें कोरोना वायरस से लड़ रहीं थी। उन्होंने कहा, ÷भारत में, सरकार के साथ-साथ, 135 करोड़ नागरिकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी। हमारी सफलता का यही कारण है।÷ उन्होंने कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने अग्रिम मोर्चे के कर्मियों, चिकित्सकों, नर्सों, एनजीओ और स्वयंसेवियों का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा, ÷गैर सरकारी संगठनों ने हर संभव तरीके से लोगों की मदद की। जब प्रवासी पिछले साल अपने घर लौट रहे थे, एनजीओ ने उन्हें खाना, पानी, आश्रय दिया और उनके गंतव्यों तक पहुंचने में मदद की। सरकार अकेले यह सब नहीं कर पाती। शाह ने कहा कि कोविड-19 के दैनिकमामलों में गिरावट आने से चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग भी घट रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जहां देश में रोजाना 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी वह कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अचानक बढञकर 10,000 मीट्रिक टन हो गई। उन्होंने बताया कि फिलहाल मांग 3,500 मीट्रिक टन है।

शाह ने बताया कि कोविड-19 मरीजों की जान बचाने के लिए जब जीवनरक्षक गैस की मांग बहुत ज्यादा थी उस वक्त केंद्र ने चिकित्सीय ऑक्सीजन और क्रायोजेनिक टैंकरों के परिवहन के लिएट्रेनों और रक्षा विमानों की सेवाएं लीं। उन्होंने कहा, ÷15,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का परिवहन रेलगाड़ियों के माध्यम से, जबकि ऑक्सीजन भंडारण के लिए टैंकरों का परिवहन सैन्य विमानों का प्रयोग कर किया गया।÷ शाह ने कहा कि कोविड-19 की पहली लहर के बाद पीएम केयर्स फंड के तहत जहां 612 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को स्वीकृति दी गई वहीं इस साल 1,051 को स्वीकृति दी गई। शाह ने बताया कि केंद्र ने पीएम केयर्स फंड के जरिए एक लाख ऑक्सीजन सांद्रकों की खरीद की।

कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लोगों को निरंतर जागरूक करने की जरूरत: योगी

लखनऊ (एजेंसी)।

कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इन सब के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नगर निगम के नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में कोरोना को लेकर भी बातें कहीं। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोगों को निरंतर जागरूक करते रहें क्योंकि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। हमने उसे कुछ हद तक नियंत्रित किया है। भीड़ ना होने दीजिए, सरकार ने जो नियम बनाएं हैं लोगों से उसका पालन करवाएं। इससे हम तीसरी लहर को आने से पहले ही नियंत्रित कर लेंगे।

आपको बता दें कि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 38000 के आसपास प्रतिदिन चले गए थे। हालांकि अब स्थिति काबू में नजर आ रही है। प्रतिदिन लगभग 15 साल के आसपास नए मामले सामने आ रहे हैं। मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी जा रही है।

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव के आचरण से अराजकता पैदा हो सकती है: सरकारी सूत्र

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 28 मई की बैठक से पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के दूर रहने पर कड़ा ऐतराज करते हुए सरकारी सूत्रों ने बुधवार को कहा कि उनके आचरण से आईएएस तंत्र को नुकसान पहुंचा है और इससे अराजकता पैदा हो सकती है। उन्होंने 28 मई को बैठक में मोदी को इंतजार कराने और प्रधानमंत्री को प्रस्तुति दिए बगैर ही बैठक स्थल से चले जाने को लेकर बंदोपाध्याय के आचरण पर सवाल उठाया।

इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, ''याद दिला दूं कि समीक्षा बैठक स्वयं प्रधानमंत्री ने की जो चक्रवात 'यास' से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बैठक के लिए पहुंचे थे।'' मोदी चक्रवात के कारण हुए नुकसान का मौके पर जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल गए थे। सूत्रों ने सवाल किया कि पीएसयू और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न संबंधित विभागों से जुड़े केंद्र सरकार के अधिकारी यदि आपदा समेत विभिन्न स्थितियों में मुख्य सचिव द्वारा बुलायी गयीं बैठकों में जाने से मना कर दें तो क्या होगा।

सूत्र ने सवाल किया, '' क्या यह संघीय ढांचे में संस्थानात्मक रूप से चीजें बिखरने जैसा नहीं होगा?'' उन्होंने सवाल किया कि क्या अलपन बंदोपाध्याय ने खुद को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की 'इच्छा' के अधीन कर लिया था, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 'पुरस्कृत' किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के निजी कर्मचारी की तरह काम नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने आईएएस अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित करते हुए उन्हें ''भारत का स्टील ढांचा'' बताया था।

सूत्रों ने कहा कि पटेल ने न केवल युवा अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए इस कथन का उपयोग किया, बल्कि इसके पीछे कई अर्थ छिपे थे कि भारत एक बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र है जहां राज्यों के शासकों के अपने स्वयं के हित और अहंकार होंगे। एक सूत्र ने कहा, ''क्या इससे अराजकता नहीं होती? अलपन बंदोपाध्याय के 28 मई के आचरण ने आईएएस को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिन्हें सरदार पटेल ने भारत का 'स्टील ढांचा' बताया था।'' उन्होंने कहा कि भारतीय संघीय ढांचे में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) शासन एवं समन्वय से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच सेतु की तरह काम करती है।

नीतीश ने 121 टीका एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, कहा- इस साल पूरा हो जाएगा टीकाकरण का काम

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

बिहार में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 121 टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमने गांव में आरटी-पीसीआर की जांच शुरू की है। उसके लिए टेस्टिंग वैन की शुरूआत करा दी गई थी। टेस्टिंग वैन के जरिए एक दिन में 1,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 5 और टेस्टिंग वैन शामिल किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि साल के अंत तक टीकाकरण का काम राज्य में पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल 18 से ऊपर वालों के लिए टीके की कमी है। केंद्र सरकार से आश्वासन मिला है कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। इससे पहले टीका एक्सप्रेस को लेकर स्वास्थ्य विभाग में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी।

मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जुड़े रहे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद, रेनू देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। इनमें से 40 टीका एक्सप्रेस यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए कई जिलों में टीका उपलब्ध कराया गया है। विभाग का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक सभी लोगों का टीकाकरण पूरा किया जाए।

कोरोना वायरस से प्रभावित बच्चों के लिए सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किये

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं और इस लिहाज से राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय ... एक को खो चुके हैं और इनमें 1,700 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता, दोनों की ही कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु हो गयी। मिश्रा ने राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की भूमिकाएं निर्धारित ...

सीएम शिवराज बोलें- कोरोना की दूसरी लहर को किया नियंत्रित, तीसरी लहर के लिए तैयारियां शुरू

भोपाल। (एजेंसी)।

देश के साथ-साथ मध्यप्रदेश में भी कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर था। हालांकि, अब मध्यप्रदेश की स्थिति काफी सुधरी हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि हमने कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारियां शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं इसलिए हमने कई जगह बच्चों के लिए वार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात कही है जो छात्र छात्राएं विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के छात्र-छात्राएं विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं इसलिए हमने फैसला किया है कि विदेश जाने से पहले उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने यह भी फैसला किया है कि जिन बच्चों की उम्र 12 वर्ष से कम है,उनके माता-पिता को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जायेगी। यदि बच्चे को कोरोना संक्रमण हुआ, तो माता-पिता का साथ रहना आवश्यक है, इसलिए उनका वैक्सीनेशन हो जाने पर वे संक्रमण से मुक्त रहेंगे।

अहिल्याबाई होलकर जीं की 296वी जयंती मनायी गई

संवाददाता जनार्दन गौड़ जौनपुर । नौपेड़वा के उतरुकला गांव में अहिल्याबाई होलकर की 296 वी जयंती बड़े धूम धाम से मनाई गई जिसमें रामधारी पाल व विनोद पाल ने क्रम से अहिल्याबाई होलकर के विषय मे प्रकाश डाले।अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत-भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बँधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए-सुधरवाए, भूखों के लिए अन्नसत्र (अन्यक्षेत्र) खोले, प्यासों के लिए प्याऊ अपने जीवनकाल में ही इन्हें जनता 'देवी' समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आँखों देखा ही कहाँ था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन-साधारण गृहस्थ, किसान मजदूर-अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा-धर्म-अंधविश्वासों, भय त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी, न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया-और बहुत किया,वह चिरस्मरणीय है। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मन्दिर , गया में विष्णु मन्दिर उनके बनवाये हुए हैं, रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथ पुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थस्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्म शालाएं खुलवायीं। अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे-से गांव से खूबसूरत शहर बनाया, मालवा में कई किले और सड़कें बनवाईं। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं और विश्राम गृह बनवाए,न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिमालय पर भी। सोमनाथ, काशी, गया, अयोध्या, द्वारका, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्रीनारायण, रामेश्वर, मथुरा और जगन्नाथपुरी इत्यादि जिसमे उपस्थित रामधारी पाल, विनोद पाल, रामअवध ,वजरंगी ,श्यामलाल,राकेश,शशिकांत,परमजीत ,सुबाष,लालजी,शोभनाथ पाल आदि लोग रहे ।

लाकर रहेंगे भारत, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर बोला विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर चल रही कोशिशों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे भारत लाने का प्रयास जारी है और इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, 'भारत इस बात पर अडिग है कि भगोड़ों को देश वापस लाया जाए। वह इस समय डोमिनिका की हिरासत में है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हम सारी कोशिशें जारी रखेंगे ताकि उसका (चोकसी का) भारत आना सुनिश्चित हो।'

विदेश मंत्रालय ने यह बातें ऐसे समय पर कही हैं जब भगोड़ा कारोबारी डोमिनिका पुलिस की हिरासत में है और मजिस्ट्रेट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। 'डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन की खबर के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में वांछित चोकसी ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उसका अपहरण किया गया था और उसे पड़ोसी देश एंटीगुआ तथा बारबुडा से जबरन डोमिनिका लाया गया। व्हीलचेयर पर बैठा, 62 वर्षीय चोकसी काले रंग की निकर और नीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए पीठासीन रोसियू मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ। उसे डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल से अदालत लाया गया। इसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे डोमिनिका उच्च न्यायालय ने अवैध प्रवेश के आरोपों का सामना करने के लिए उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए दायर की जाती है जो गिरफ्तार है या अवैध रूप से हिरासत में है।

... बाद हिमाचल में भी धार्मिक यात्राओं पर अनिश्चितता के बादल

...अब हिमाचल प्रदेश ...थगित हों चूंकि अभी ...इस मामले पर कोई ...र नाथ यात्रा की तरह ...त्र श्रीखंड महादेव, ... कैलाश यात्रा का ...ह में होता है। यात्रा के ...ने लाखों की तादाद में ...नीय लोगों का भी ...ता है। बीते साल इन ...ओं पर सरकार ने रोक ... हालांकि सरकार ने अनलाक प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन अभी तक न तो मंदिरों के खोलने न ही धार्मिक यात्राओं के आयोजन पर कोई फैसला हो पाया है। किन्नर कैलाश जाने वाले यात्री भी सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। जिससे असमंजस का महौल बना हुआ है प्रदेश की ऐतिहासिक एवं धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा पर इस वर्ष भी कोरोना के चलते संकट के बादल हैं। हर साल 15 से 31 जुलाई तक जिला प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड महादेव यात्रा होती है। कुल्लू की जिलाधीष डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि श्रीखंड यात्रा पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते रहे तो श्रीखंड यात्रा नहीं होगी। एसडीएम आनी चेत सिंह के अनुसार इस बार भी यात्रा होने की संभावनाएं कम हैं। उधर, पवित्र मणिमहेश यात्रा पर भी असमंजस है। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि जून-जुलाई में होने वाले मिंजर मेले और मणिमहेश यात्रा को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक से 20 अगस्त तक चलने वाली किन्नर कैलाश यात्रा पर भी संकट के बादल हैं। सिरमौर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार की यात्रा पहले से ही प्रतिबंधित है। हालांकि, 15 अप्रैल को मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध है। चूड़धार में खाने-पीने व ठहरने की भी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। मंडी जिले में 13-14 जून को नाचन और द्रंग क्षेत्रों में होने वाले सरानौहली (बकरयाले रा साजा) मेले का आयोजन स्थगित हो गया है। 10 जुलाई को नाचन के सरोआ धार स्थित माता जालपा और माता हाटेश्वरी मंदिर हटगढ़ में लगने वाला मेला भी कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं।

सार समाचार

म्यांमार सैन्य तख्तापलट की रिपोर्टिंग कर रहे दो पत्रकारों को सुनाई गई जेल की सजा

बैंकॉक। म्यांमार की एक सैन्य अदालत ने दो पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग को लेकर दो साल जेल की सजा सुनाई है। विभिन्न अधिकार समूहों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह देश में हुए तख्तापलट के बाद स्वतंत्र प्रेस पर एक और हमला है। दक्षिणी म्यांमा के शहर माइक में अदालत ने बुधवार को 'डेमोक्रेटिक वॉयस ऑफ बर्मा' के रिपोर्टर आंग क्याव (31) और ऑनलाइन समाचार एजेंसी 'मिजिमा' के फीलांस रिपोर्टर जॉ जॉ (38) को सजा सुनायी। म्यांमार के 'असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स' के अनुसार, सैन्य तख्तापलट के बाद करीब 90 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से आधे से ज्यादा अब भी हिरासत में हैं जबकि 33 पत्रकार भूमिगत हैं। दोनों पत्रकारों के परिवारों के सदस्यों को सैन्य अदालत में सुनवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गयी थी। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कुछ मिनट के लिए फोन पर परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की अनुमति दी गयी।

जेल से बेलारूस पत्रकार ने बनाया अपना वीडियो, कहा- मुझे फंसाया जा रहा है

कीव। बेलारूस द्वारा एक विमान को जबरन अपने यहां उतरवाकर गिरफ्तार किये गए विरोधी पत्रकार ने जेल से एक वीडियो में कहा कि उसे एक अज्ञात सहयोगी द्वारा फंसाया गया है। रमन प्रातसेविच की फुटेज सरकारी नियंत्रण वाले ओएनटी चैनल पर बुधवार रात प्रसारित एक टीवी कार्यक्रम का हिस्सा थी। इस कार्यक्रम में 26 वर्षीय प्रातसेविच को यह कहते हुए भी दिखाया गया है कि बेलारूस के सत्तावादी राष्ट्रपति एलेग्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन अब कड़ी कार्रवाई के बीच निरर्थक है और सुझाव दिया कि विपक्ष अब और उचित अवसर की प्रतीक्षा करे। प्रातसेविच के एक शीर्ष सहयोगी ने कहा कि पत्रकार स्पष्ट रूप से दबाव में बोल रहा था। टीवी कार्यक्रम में दावा किया गया कि बेलारूस के अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रातसेविच रयान एयर के विमान में सवार था जो यूनान से विलनियस जा रहा था जब विमान नियंत्रक ने बम होने का उल्लेख करते हुए 23 मई को इसे मिन्स्क में उतरवाया था। विमान में कोई बम नहीं मिला था लेकिन प्रातसेविच को उसकी रूसी महिला मित्र के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। विमान का मार्ग परिवर्तन किये जाने से यूरोपीय संघ नाराज था और उसने बेलारूस के सभी विमानों के अपने हवाईक्षेत्र से होकर गुजरने पर रोक लगा दी। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने अपने विमानों को बेलारूस के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने की सलाह दी और बेलारूस की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले नए प्रतिबंधों को लगाने की तैयारी की जा रही है।

ईरान की राजधानी के पास तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग

तेहरान। ईरान की राजधानी के पास स्थित एक तेल रिफाइनरी में बुधवार को लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी प्रयास कर रहे हैं। तेहरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित सरकारी तोंदगूयान पेट्रोकेमिकल कंपनी में बुधवार की रात आग लगी। तेल मंत्रालय की शना समाचार एजेंसी ने बताया कि रिफाइनरी के दो वेस्ट टैंक (कचरा रखने वाला टैंक) में रिसाव के कारण आग लगी। शुरुआत में अधिकारियों ने आशंका जतायी थी कि आग लगने से रिफाइनरी के तरल पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन प्रभावित हुआ है। ईरान के तेल मंत्री बिजन जांगनेह रात को ही मौके पर पहुंचे थे। उधर, आपूर्ति बाधित नहीं होने के सरकार के आश्वासन के बावजूद बृहस्पतिवार (इस्लामी सप्ताहांत, बृहस्पतिवार, शुक्रवार) सुबह से ही लोग गैसोलिन के लिए लंबी-लंबी लाइनों में खड़े दिखे। सना ने रिफाइनरी के प्रवक्ता शाकिर खाफेई के हवाले से बताया कि प्रशासन को आशा है कि ईंधन समाप्त होने के बाद आग खुद-ब-खुद बुझ जाएगी।

कोरोना वैक्सीन पर हुई रिसर्च, बूस्टर शॉट की पड़ सकती है जरूरत

न्यूयॉर्क। विश्व में कोविड-19 के सबसे सफल टीकों के 'बूस्टर शॉट' बार-बार दिए जाने पर यह संक्रमण से स्थायी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 'बूस्टर शॉट' से तात्पर्य टीके की निर्धारित खुराक से अतिरिक्त खुराक देने से है। शरीर में संक्रमण के अवशेषों पर अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। बहरहाल, उनका कहना है कि इसके लिए अधिक अनुसंधान की आवश्यकता हैं और 'वायरस म्यूटेशन' अब भी एक 'वाइल्ड कार्ड' है। 'क्लीनिकल' अनुसंधान अब भी जारी है और इस बात के सबूत मिले हैं कि 'फाइज़र' और 'मॉर्डना' द्वारा निर्मित एमआरएनए टीकों से बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, विशेष रूप से 'एंटीबॉडी' पर निर्भर नहीं है जो समय के साथ कम हो जाती है। शरीर में प्रतिरक्षा की कई परत होती हैं, जो अतिरिक्त सुरक्षा (बैकअप) प्रदान करती हैं।
वैज्ञानिकों को अभी यह नहीं पता कि उस सुरक्षा के सहसंबंध को क्या कहा जाता है, जिस स्तर से नीचे 'एंटीबॉडी' अतिरिक्त सहायता के बिना कोरोना वायरस से बचाव नहीं कर सकती। अमेरिका में संक्रामक रोग के विशेषज्ञ डॉ. एंथोनी फाउची ने पिछले सप्ताह कहा था कि टीके से अनंतकाल के लिए सुरक्षा नहीं मिल सकती। 'फाइजर' और 'मॉर्डना' के अधिकारियों ने बताया कि लोगों को शायद अन्य संक्रामक रोग की तरह हर साल इसके टीके लेने पड़ सकते हैं। कम्पनियों की योजना इसके लिए कुछ उम्मीदवारों को तैयार रखने की है, लेकिन कम्पनियों नेइसका फैसला अभी नहीं किया है कि ये 'बूस्टर शॉट' कब दिए जाएंगे।

वुहान लैब को फंड कर रहा था अमेरिका? 866 पन्नों वाले ईमेल चैट में अहम खुलासा!

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

दुनियाभर में पिछले डेढ़ साल से कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए, जबकि लाखों लोगों की जान चली गई। वहीं चीन पर कोरोना वायरस को प्रयोगशाला में बनाने के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच महामारी विशेषज्ञ और राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष स्वास्थ्य सलाहकार डॉ. एंथनी फाउची और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स के ऊपर बड़ा आरोप लगा है। अमेरिकी समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट के हाथ लगे डॉ. फाउची के ईमेल के जरिये आरोप लगाए गए हैं कि दोनों ने वुहान लैब को पैसे दिए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने डॉ.फाउची के 866 पन्नों वाला ईमेल चैट को हासिल किया। इसमें जानकारी मिली है कि अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ और चीनी वैज्ञानिकों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी।

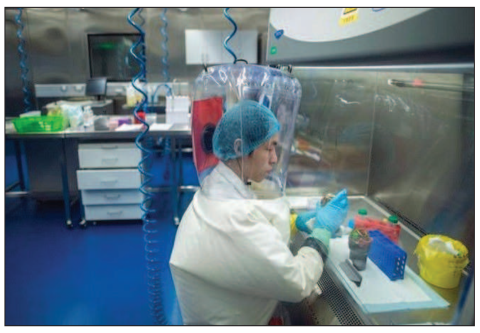

क्या डॉ. फाउची का वुहान लैब की फंडिंग में हाथ था?

आरोप है कि एनआईएच ने इको हेल्थ एलायंस को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च के लिए फंडिग की थी। रिसर्च का काम था नेचर से निकलने वाले ऐसे-ऐसे वायरस के बारे में पता लगाना जो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। पहली बार एनआईएच से ऐसी रिसर्च की फंडिंग साल 2014 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में शुरू हुई। पीटर डचैक ने दिसंबर 2019 में दिए इंटरव्यू में कहा था कि हम कई सालों से सार्स वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। पीटर डचैक ने बताया था कि सार्स वायरस में प्रोटीन को मैन्युपुलेट करके देख रहे हैं कि वो कैसे इंसानों को इंपैक्ट कर सकता है और उसकी वैक्सीन क्या हो सकती है। पिछले साल अगस्त में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एनआईएच ने ईको हेल्थ एलायंस की फंडिंग सस्पेंड कर दी। एनआईएछ ने कहा था कि जब तक ईको हेल्थ एलायंस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की आउटसाइड एजेंसी से इंस्पेक्शन नहीं कराता।

पिछले साल मई में 77 नोबल प्राइज विनर और 31 साइंटिफिक सोसायटी ने एनआईएच को खत लिखकर ईको हेल्थ एलायंस की रद्द की गई फंडिंग को फिर से रिव्यू करने की मांग की थी। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि इन चिट्ठियों के पीछे भी पीटर डचैक का हाथ है।

नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने इटली के ट्यूरिन शहर और हिमालय की लुभावनी तस्वीरें साझा की

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अगर आप हर रोज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो संभावना है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से ली गई पृथ्वी की विभिन्न तस्वीरों को देखा होगा। अद्भुत,' 'मनमोहक,' और 'सुंदर,' ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल लोग इन तस्वीरों को देखकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) ने ग्रह के साथ-साथ अंतरिक्ष में अन्य प्लेनट की कुछ लुभावनी तस्वीरें साझा की है जिसके बाद ट्विटर में लोग इन तस्वीरों को रिट्वीट करते थक नहीं रहे है। नासा के अंतरिक्ष यात्री और आईएसएस के लिए फ्लाइट इंजीनियर मार्क टी. वंदे हे ने बर्फ से ढके हिमालय की एक तस्वीर साझा की और इसे कैप्शन दिया: 'हिमालय में साफ और चमकता दिन' लेकिन मार्क अकेले नहीं थे जिन्होंने आईएसएस से ली गई तस्वीर को साझा किया था। शेन किम्ब्रू, एक

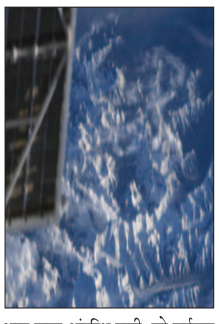

अन्य नासा अंतरिक्ष यात्री, जो वर्तमान में आईएसएस पर सवार है, ने इटली के एक शहर ट्यूरिन की एक मनोरम रात की तस्वीर पोस्ट की। तस्वीरों को साझा किए जाने के तुरंत बाद, माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर लोगों ने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की सराहना की और अंतरिक्ष से ग्रह के दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मार्क हेई के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कई ट्विटर यूजर ने तस्वीरों की प्रशंसा की है।

छीन सकती है नेतन्याहू की कुर्सी, इजराइल में सरकार बनाने के लिये विरोधी विचारधारा के दल एकजुट हुए

यरुशलम। (एजेंसी)।

करीब दो हफ्ते पहले जब इजराइल देश में सबसे बुरे सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था, गाजा से रॉकेटों की बौछार हो रही थी, तब कौन सोच सकता था कि वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी जैसी विरोधी विचारधाराओं वाले दल अरब पार्टी के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने के लिए सहमत होंगे जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करेगी। हाल में जब लड़ाई तेज हुई तब सभी यह सोच रहे थे कि इससे इजराइल में सबसे लंबे समय तक पद पर रहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सत्ता पर काबिज रहने के लिये थोड़ी और मोहलत मिल जाएगी क्योंकि उन्हें सत्ता से दूर करने के लिये बेचैन राजनीतिक दलों ने बातचीत से दूरी बना ली थी।

जब लड़ाई जारी रही तब विपक्षी गठबंधन की सरकार बनाने की जिम्मेदारी उठा रहे येश अतीद पार्टी के नेता याइर लापिद (57) और राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन की सरकार बनाने की उम्मीद धूमिल होने लगी। हालांकि, एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में जिस व्यक्ति को सरकार बनाने की विपक्षी कवायद के पटरी से उतरने से सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा था वही इन ताकतों को एकजुट करने में सबसे अहम कड़ी भी बनकर उभरा। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि कई लोगों द्वारा इजराइल के 'डिवाइडर इन चीफ' के तौर पर देखे जाने वाले 71 वर्षीय नेतन्याहू ही एक अलग अंदाज में अपने विरोधियों को एकजुट करने वाले भी साबित हुए जिनके कारण इजराइल के इतिहास में जिन लोगों के एक साथ आने की कल्पना भी नहीं की गई थी वे राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने के लिये मिल गए।

लापिद द्वारा राष्ट्रपति रिवलिन को गठबंधन को एकजुट रखने में कामयाबी मिलने की खबर देने से घंटों पहले दैनिक 'हारेट्ज' के पत्रकार अंशेल प्फेफ्फर ने कहा, 'आज रात जो हुआ और विश्वास मत अगर होता है तो उसमें जितने भी दिन बचे हैं उससे पहले, यह एक ऐतिहासिक तस्वीर है। अरब- इजराइली पार्टी के नेता और जूइश-नेशनलिस्ट पार्टी के नेता एक साथ सरकार में शामिल होने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।' उन्होंने राम पार्टी के प्रमुख मंसूर अब्बास की दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नफ़्ताली बेनेट और मध्यमार्गी येश अतीद पार्टी के याइर लापिद की समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए एक तस्वीर भी अपने ट्वीट के साथ पोस्ट की। यह तस्वीर बृहस्पतिवार को हर किसी के बीच चर्चा का विषय थी और आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर ज्यादा तवज्जो दिये बगैर सभी मीडिया संस्थान इस 'ऐतिहासिक पल' के बारे में बात तर रहे थे।

देश की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में लापिद के पास 61 सांसदों के समर्थन के साथ बेहद मामूली बहुमत है जबकि सामने चुनौतियां कई हैं लेकिन उसे उम्मीद है कि यह बहुमत मजबूती के साथ कायम रहेगा क्योंकि इसके पीछे 2009 से लगातार 12 सालों से देश की निर्बाध रूप से कमान संभाल रहे नेतन्याहू को हटाने का 'एकजुटता का उद्देश्य' है। नेतन्याहू इजराइल के

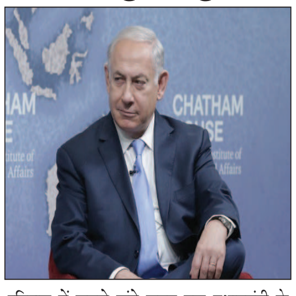

इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले नेता हैं जिन्होंने देश के संस्थापक डेविड बेन गुरियन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। रोचक बात यह है कि नेतन्याहू को पद से हटाने के लिये एकजुट हुए लोगों में से एक तिहाई वैचारिक तौर पर उनके 'प्राकृतिक सहयोगी' हैं और पूर्व में उनके करीबी सहयोगियों के तौर पर काम भी कर चुके हैं।

सोशल मीडिया साइट पर पहले ही बैन है डोनाल्ड ट्रंप, अब ब्लॉग पेज भी हुआ बंद

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ब्लॉग स्थायी रूप से बंद कर दिया है। फेसबुक और ट्विटर सहित विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद ट्रंप इसी वेब पेज के जरिए अपने तीखे भाषणों और बयानों को साझा करते थे। उनके प्रवक्ता जेसन मिलर ने बुधवार को सीएनबीसी न्यूज से कहा कि ट्रम्प की वेबसाइट से फ्रॉम दि डेस्क ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप'' नामक पेज को हटा दिया गया है। इस पेज को एक महीने से भी कम समय पहले शुरू किया गया था। मिलर ने कहा, यह हमारे व्यापक प्रयासों के लिए सिर्फ सहायक था और हम काम कर रहे हैं... वेबपेज वापस नहीं आएगा।'' उन्होंने कहा कि जल्द ही व्यापक प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है, लेकिन उन्हें समय के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। यह पूछे जाने पर कि, क्या यह कदम 74 वर्षीय ट्रंप द्वारा किसी अन्य सोशल मीडिया मंच से जुड़ने के लिए पहला कदम है, मिलर ने कहा- हाँ, वास्तव में, ऐसा ही है। '' उन्होंने लोगों से प्रतीक्षा करने को कहा।

कैथोलिक स्कूल में मिले 215 शवों को लेकर कनाडा के मंत्री ने पोप से की माफी की मांग

टोरंटो। (एजेंसी)।

कनाडा के आदिवासी सेवा मंत्री ने ब्रिटिश कोलंबिया के कैमलूप्स में आदिवासियों के एक पूर्व आवासीय स्कूल में दफनाए गए 215 बच्चों के शव मिलने की घटना के मद्देनजर बुधवार को कहा कि पोप फ्रांसिस को कनाडा की आवासीय स्कूल प्रणाली में कैथोलिक चर्च की भूमिका के लिए औपचारिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए पूर्व आवासीय स्कूलों में अब तक चिह्नित नहीं हो पाई कब्रों का पता लगाने के प्रयासों को समर्थन देने का फिर से संकल्प लिया। ब्रिटिश कोलंबिया के सैलिश बोलने वाले एक समूह फर्स्ट नेशन की प्रमुख रोसेन कैसमिर ने कहा कि जमीन के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने वाले रडार की मदद से 215 बच्चों के शव मिले। इनमें कुछ तीन वर्ष की उम्र के बच्चों के शव हैं। गौरतलब है कि 19वीं सदी से 1970 के दशक तक फर्स्ट नेशन के 1,50,000 से अधिक बच्चों को कनाडाई समाज में अपनाने के कार्यक्रम के तौर पर सरकार के वित्त पोषण वाले ईसाई स्कूलों में पढ़ना होता था। उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए विवश किया जाता और अपनी मातृ बोलने नहीं दी जाती थी। कई बच्चों को पीटा जाता था तथा उन्हें अपशब्द कहे जाते और ऐसा बताया जाता है कि उस दौरान 6,000 बच्चों की मौत हो गयी थी। कैमलूप्स स्कूल 1890 से 1969 तक संचालित हुआ था। इसके बाद संघीय सरकार ने कैथलिक चर्च से इसका संचालन अपने हाथों में ले लिया। यह स्कूल 1978 में बंद हो गया था। ट्रूथ एंड रिकांसिलिएशन कमीशन ने पांच वर्ष पहले संस्थान में बच्चों के साथ हुए

दुर्व्यवहार पर विस्तृत रिपोर्ट दी थी। ट्रूथ एंड रिकांसिलिएशन कमीशन ने जो 94 सिफारिशें की थी, उनमें पोप से माफी की मांग भी शामिल है। ट्रूडो ने 2017 में वैटिकन की यात्रा के दौरान पोप से ऐसा करने का आग्रह किया था। कैथोलिक बिशप के कनाडाई सम्मेलन ने 2018 में घोषणा की थी कि पोप आवासीय स्कूलों के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी नहीं मांग सकते। हालांकि पोप दुनिया भर के आदिवासी लोगों के साथ होने वाले अन्याय को समझते हैं। आदिवासी सेवा मंत्री मार्क मिलर ने कहा, ''मुझे लगता है कि यह शर्मनाक है कि ऐसा अभी तक नहीं किया गया है।'' उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी कनाडा के कैथोलिक बिशप के कंधों पर है। आदिवासी संबंध मंत्री कैरोलिन बेनेट ने कहा कि पोप के माफी मांगने से उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगेगा, जिन्होंने कष्ट सहे हैं। उन्होंने कहा, ''वे पोप की माफी सुनना चाहते हैं।

चीन ने नयी पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह का किया सफल प्रक्षेपण

बीजिंग। चीन ने नयी पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में बृहस्पतिवार को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इस उपग्रह का इस्तेमाल मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्र में किया जाएगा। सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' ने बताया कि उपग्रह 'फेंगयुन-4बी' (एफवाई-4बी) को सिचुआन प्रांत में शिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च-3बी रॉकेट की मदद से बृहस्पतिवार तड़के प्रक्षेपित किया गया। इसमें बताया गया कि चीन की नयी पीढ़ी के पहले मौसम संबंधी उपग्रह एफवाई-4बी का इस्तेमाल मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान तथा पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्र में किया जाएगा। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (सीएनएए) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नया उपग्रह चीन के निगरानी तंत्र और छोटे तथा मध्यम स्तर की आपदाओं से निपटने की क्षमताओं को मजबूत करेगा। इसके साथ ही यह मौसम विज्ञान, कृषि, विमानन, समुद्र तथा पर्यावरणीय संरक्षण समेत कई क्षेत्रों के लिए सूचना सुरक्षा सेवाएं मुहैया कराएगा। 'ग्लोबल टाइम्स' अखबार ने बताया कि यह उपग्रह एशिया, मध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र तथा हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रखने में सक्षम है जिससे चीन की तूफान तथा चक्रवात समेत विषम मौसम परिस्थितियों के सटीक पूर्वानुमान की क्षमताएं बढ़ेंगी।

भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए खबर! ग्रीन कार्ड की सीमा हटाने वाला विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में हुआ पेश

वाशिंगटन।अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में दोनों दलों ने हर देश को दिए जाने वाले रोजगार पर आधारित ग्रीन कार्ड की सीमा हटाने के लिए संयुक्त रूप से एक विधेयक पेश किया। कांग्रेस सदस्य जोए लोफग्रेन और जॉन कुर्टिस ने यह विधेयक पेश किया और इससे भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 'इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट' (ईएजीएलई) कानून, 2021 को पहले सीनेट में पारित करने की जरूरत है जिसके बाद

वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस में जाएगा। इस विधेयक में रोजगार आधारित प्रवासी वीजा पर प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा को हटाने का प्रावधान है। साथ ही इसमें परिवार प्रायोजित वीजा पर प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा को 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। आव्रजन और नागरिकता पर सदन की उप समिति की अध्यक्ष लोफग्रेन ने कहा, ''हम सभी जानते हैं कि हमारी आव्रजन प्रणाली में बहुत खामी है और इसमें दशकों से त्रुटि है।'' उन्होंने कहा कि आव्रजन वीजा देने की मूल रूपरेखा 20वीं सदी की है और इसे आखिरी बार गंभीर रूप से 1990 में संशोधित किया गया जब संसद ने वीजा के आवंटन पर दुनियाभर में एक सीमा तय कर दी और प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा आज भी लागू है। उन्होंने कहा कि समय के साथ ही इन सीमाओं से 1990 में ग्रीन कार्ड पाने का इंतजार कर रहे लोगों की संख्या अकल्पनीय रूप से बढ़ गयी। इसका असर यह हुआ कि कम आबादी वाले देशों को भी उतने ही वीजा आवंटित किए गए जितने वीजा ज्यादा आबादी वाले देशों को मिले।

तेजी से पिघल रहे हैं हिमालयी रेंज में ग्लेशियर और बर्फ, डब्ल्यूएचओ ने दी यह चेतावनी

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

इंसानी गतिविधियों के कारण 'ब्लैक कार्बन' बढ़ने से संवेदनशील हिमालयी श्रृंखला में हिमनद और बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं और इससे तापमान बदल रहा है तथा बारिश की प्रवृत्ति (पैटर्न) बदल रही है। विश्व बैंक ने बृहस्पतिवार को प्रकाशित अपने एक अहम अध्ययन में यह बात कही। हालिया साक्ष्यों से यह संकेत मिले हैं कि तापमान और बारिश की प्रवृत्ति को प्रभावित करने के अलावा मानव जनित ब्लैक कार्बन की वजह से इन पर्वत श्रृंखलाओं में हिमनद और बर्फ के पिघलने की गति और बढ़ गई है। ब्लैक कार्बन दरअसल जीवाश्म और अन्य जैव ईंधनों के अपूर्ण दहन की वजह से उत्सर्जित कणिकीय पदार्थ (पर्टिकुलेटेड मैटर) हैं, जो वायुमंडल का ताप बढ़ाते हैं। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के उपाध्यक्ष हार्टविग शाफर के मुताबिक, यह दक्षिण एशिया के अंदर और बाहर मानवीय गतिविधियों से पैदा होता है। यह हवा में मौजूद कणों का बड़ा हिस्सा है जो जलवायु परिवर्तन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। 'ग्लेशियर ऑफद हिमालयाज' अध्ययन इस बात के नए साक्ष्य प्रदान करता है कि बदलती वैश्विक जलवायु के संदर्भ में दक्षिण एशियाई देशों की ब्लैक कार्बन को कम करने की नीतियों का हिमालय, कराकोरम और हिंदु कुश पर्वत श्रृंखलाओं में हिमनदों के बनने और पिघलने पर किस हद तक प्रभाव पड़ता है। शाफर ने कहा कि यह जल संसाधनों की सीमा और नदी घाटियों पर हिमनदी के इस नुकसान के संभावित प्रभाव का भी आकलन करता है। करीब 140 पन्नों के इस अध्ययन में तर्कपूर्ण नीति बनाने के उद्देश्य से 2040 तक के परिदृश्य को भी पेश किया गया है।

शाफर ने कहा, 'हिमालय में एक हिमनद टूटने से अचानक आई हालिया विनाशकारी बाढ़ जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव और उन खतरों को लेकर हमें आगाह करती है जिनसे हमें बचना है।' उन्होंने कहा, 'जैसे-जैसे हिमनद सिकुड़ते हैं नीचे की ओर कई लोगों का जीवन व आजीविका जलापूर्ति के प्रवाह में बदलाव के कारण प्रभावित होते हैं। हम बर्फ को तेजी से पिघलाने के लिये जिम्मेदार ब्लैक कार्बन को जमा होने से रोकने के लिये सामूहिक प्रयास कर हिमनद के पिघलने की गति को धीमा कर सकते हैं। इस संसाधनों को बचाने के लिये क्षेत्रीय सहयोग क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिये महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक होगा।' विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के मुख्य अर्थशास्त्री और अध्ययन के मुख्य लेखक मुथुकुमार मणि ने कहा, 'जल संसाधन प्रबंधन नीतियां अवश्य बनाई जानी चाहिए क्योंकि हम जिन प्रवृत्तियों को देख रहे हैं वे एक अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण भविष्य की तरफ इशारा कर रही हैं।

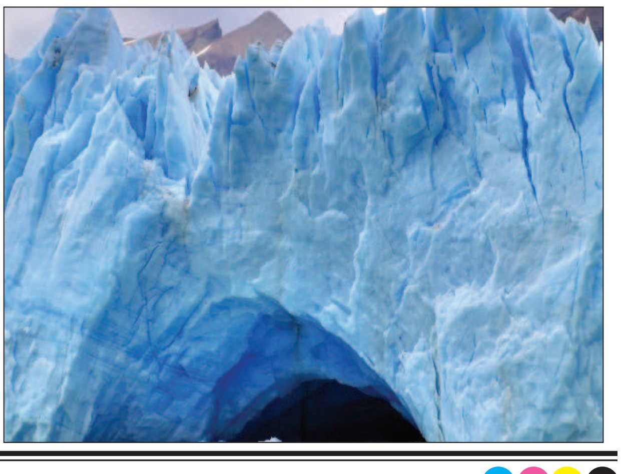

संपादकीय

प्रभु-प्रेम के व्यक्त स्वरूप - संत दर्शन सिंह जी महाराज

सावन कृपाल रूहानी मिशन के प्रमुख संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की 32वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यू-ट्यूब पर शिकागो, अमेरिका से लाइव टेलीकास्ट के ज़रिये अपना पावन संदेश समस्त मानव जाति को दिया।

उनके सत्संग से पूर्व पूजनीया माता रीटा जी ने दादू साहब की रब्बी वाणी से च्चअजहूं न निकसे प्राण कठोरज्ज का गायन किया। उसके पश्चात संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने गरमाया कि, च्चसंत दर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत का रास्ता लाखों-करोड़ों लोगों को समझाया। जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो उनका दिव्य-प्रेम, उनकी करूणा और दया हमें उनकी ओर बार-बार खींचती है।

संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम ज़िंदगी के मकसद को जानें और जीते-जी इसी जीवन में अपनी मंज़िल तक पहुँचें। यह मानव चोला एक सुनहरा अवसर है अपने आपको जानने और पिता-परमेश्वर को पाने के लिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज जैसे महापुरुष इस धरती पर आते हैं ताकि हमारा यह मकसद पूरा हो। ऐसे महापुरुष जब भी आते हैं तो वो अपने प्रेम के ज़रिये हम सब की ज़िंदगी में एक बदलाव ले आते हैं।

आज से 32 साल पहले संत दर्शन सिंह जी महाराज महासमाधि में चले गए लेकिन उनकी शिक्षा और प्रेम सदा-सदा के लिए हमारे साथ रहेगा। वो चाहते थे कि हम इस मनुष्य जन्म का पूरा-पूरा फायदा उठाएं और अपने जीवन के ध्येय को पूरा करें। इसके लिए जो वो रास्ता हमें दिखा गए हैं, उस रास्ते पर हम सबको तेजी से कदम बढ़ाने चाहियें।

इस अवसर पर शांति अवेदना सदन, राज नगर नई दिल्ली में कैंसर पीड़ित रोगियों को, बदरपुर स्थित गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को और इब्राहिम पुर, बुराड़ी में स्थित श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठ में बच्चों को मिशन की ओर से दवाईयाँ, फल-सब्जियाँ व अन्य उपयोगी वस्तुओं का मुफ्त वितरण किया गया।

मिशन और जीवन कार्य - संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के नाम पर च्चसावन कृपाल रूहानी मिशनज्ज की स्थापना की। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने संत-मत की पुरानतन तालीम को न सिर्फ एक सरल और सहज तरीके से पेश किया बल्कि इसका निजानुभव भी लाखों लोगों को कराया।

संत दर्शन सिंह जी महाराज इस बात पर जोर दिया करते थे कि अध्यात्म, एक सकारात्मक एवं व्यावहारिक मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार, समाज, और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हुए आध्यात्मिक रास्ते पर तरक्की कर सकता है।

संत दर्शन सिंह जी महाराज को उर्दू और फारसी की अपनी ग़ज़लों के कारण उन्हें भारत के एक महान सूफी शायर के रूप में जाना जाता है। उनको दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की उर्दू अकादमियों द्वारा चार बार पुरस्कृत किया गया।

दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के 30 मई, 1989 को महासमाधि में लीन होने के पश्चात उनके रूहानी कार्यभार को संत राजिन्दर सिंह जी महाराज ने संभाला और आज वे उनके द्वारा दी गई संत-मत की शिक्षा को संपूर्ण विष्वभर में फैला रहे हैं। जिसके फलस्वरूप उन्हें विभिन्न देशों द्वारा अनेक शांति पुरस्कारों व सम्मानों के साथ-साथ पाँच डॉक्टरेट की उपाधियों से भी सम्मानित किया जा चुका है।

सावन कृपाल रूहानी मिशन के संपूर्ण विश्व में लगभग 3000 से अधिक केन्द्र स्थापित हैं तथा मिशन का साहित्य विश्व की 55 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। इसका मुख्यालय विजय नगर, दिल्ली में है तथा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नेपरविले, अमेरिका में स्थित है।

'आज के ट्वीट

प्रयास

कोविड महामारी की गंभीर चुनौती के बीच भी राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ गुड गवर्नेंस देने का प्रयास किया है। जनता से किये वादों को हमारी सरकार पूरे संकल्प के साथ धरातल पर उतार रही है। हमारा प्रयास है जो भी विकास कार्य प्रारंभ हो,वे तय समय सीमा में पूरे हों. - मु. अशोक गहलोत

कोविड संकट का दूसरा अभिशाप मेडिकल कचरा

हर्षदेव

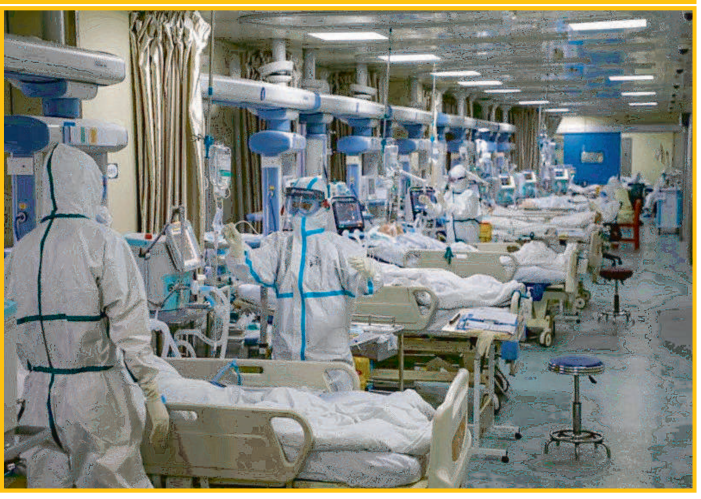

कोरोना महामारी हज़ारों टन संक्रामक कचरे की विकट समस्या भी साथ लाई है। मरीजों के इलाज, दवा और अस्पतालों के प्रबंधन तथा संक्रमण की जांच के साथ ही हर दिन हज़ारों टन ज़हरीले मेडिकल कचरे के निपटारे की चुनौती से भी शासन-प्रशासन को जूझना पड़ रहा है। हमारी धरती तो पहले ही भयंकर प्रदूषण के बोझ से कराह रही थी कि कोरोना की बीमारी का उगला हुआ कचरा प्रशासनिक प्रबंधन का दम निकाले दे रहा है। राजधानी में गाजीपुर बॉर्डर पर कचरे का विशाल पहाड़ दो दशक से इस सच्चाई का गवाह है कि कचरा निपटाने की चुनौती कितनी विकट है। तमाम विशेषज्ञों की माथापच्ची के बावजूद कचरे का यह पर्वत वहीं खड़ा पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मेडिकल कचरा वह है जो मनुष्य या पशु के इलाज के दौरान अस्पतालों से निकलता है। इसका सही निपटारा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक जरूरी शर्त है। कोरोना जैसी छूत की बीमारी के चलते तो यह और भी आवश्यक है। संक्रमण वाली बीमारियों का कचरा इसलिए गम्भीर चिंता का सबब होता है क्योंकि वह बीमारी की रोकथाम के तमाम उपायों को निरर्थक कर सकता है। उसके कारण रोग नए क्षेत्रों में आसानी से पहुंच बना सकता है। गत दिसम्बर में विशेषज्ञों का अनुमान था कि कोरोना की वजह से 146 टन कचरे के निस्तारण का काम बढ़ गया है। उस समय दिल्ली का रोजाना का कचरा 321 टन बताया गया था। लेकिन दूसरी लहर के प्रकोप के बाद इसमें एक हजार गुना तक इजाफा हो जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि, इस कचरे की तादाद का अभी तक कोई मोटा अनुमान भी नहीं किया गया है। कोरोना से जुड़े मेडिकल कचरे में सिर के कैप, मास्क, जख्मों से हटाई गई पट्टियां, पैथोलॉजिकल कचरा, ऑक्सीजन में इस्तेमाल किट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑपरेट करके शरीर से निकाले गए अंग, एक्सपायर हो चुकी दवाएं और रेडियोएक्टिव वस्तुएं शामिल हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देशभर में कोविड कचरे के निपटारे के लिए निर्देश जारी किए हुए हैं। उन निर्देशों के आधार पर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने भी नियम घोषित किए हुए हैं। कोरोना मरीजों के क्वारंटीन रहने के दौरान भी कचरा पैदा होता है। कोरोना की पहली लहर में जून से सितम्बर के बीच 18 हजार टन कचरा पैदा हुआ था। यह आकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार है। प्रदूषण समस्या पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक निगम कर्मचारी घरों से निकलने वाले कचरे के साथ ही मेडिकल कचरे को मिला देते हैं और उसको शहर से बाहर खुले में ही डाल देते हैं। यह माइक्रोप्लास्टिक्स मिला कचरा खेतों से लेकर नदियों तक पहुंचता है और इसके बाद हवा और खाने का हिस्सा बन जाता है। भारत में पिछले कुछ ही समय से अस्पतालों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना शुरू हुआ है। इसीलिए अभी तक अस्पतालों में ऑक्सीजन के अपने संयंत्र भी नहीं हैं और उनको बाहर से आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। यही स्थिति कचरे के निस्तारण के मामले में है। सभी अस्पतालों को कचरे के निस्तारण के लिए भी सरकारी धमन भट्टी पर निर्भर रहना होता है। उनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के निर्देशों पर भी चलना होता है। वे अपने कचरे को निगम एजेंसी के हवाले करके छुट्टी पा जाते हैं। समस्या उस कचरे के सही और सुरक्षित तरीके से निस्तारण की निगरानी की है। चूक इसी मामले में हो रही है। पर्यावरणविद जयधर गुप्ता जोर देकर कहते हैं कि कोरोना के कचरे के निपटान के बारे में जागरूकता की बहुत जरूरत है। इसके लिए सरकारों को अख़बारों में विज्ञापन छपवाने चाहिए। इस चेतना के अभाव में न केवल प्रदूषण से बड़ा खतरा संक्रमण का है, वरन् यह पूरे सफाई तंत्र की उपयोगिता को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। प्रदूषण विशेषज्ञों के अनुसार कचरे के निपटान का काम करने वाले सफाईकर्मियों को खास सावधानी की जरूरत है क्योंकि वह हाशिये पर रहने वाला समुदाय है और अक्सर बचाव से जुड़ी सुविधाओं के मामले में वह अनभिज्ञ रहता है। उसमें जागरूकता की कमी रहती है और किसी प्रकार के प्रशिक्षण का मौका भी उसको नहीं मिल पाता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में करीब 50 लाख सफाईकर्मी हैं। इनमें महिलाओं की संख्या आधी है। कचरा निस्तारण का सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि घनी आबादी वाले इलाकों में जरूरी नियमों और निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है क्योंकि निगरानी के नाम पर कर्मचारियों को चेतावनी देकर जिम्मेदारी पूरी कर ली जाती है। प्रदूषण विशेषज्ञों ने इस कचरे के निस्तारण के लिए चार सूत्री निर्देश तैयार किए हैं। ये हैं—कचरे की व्यवस्था पर सोचो, मेडिकल कचरे को अलग रखो, उसकी तादाद कम से कम रखो और उसके पुनः उपयोग की व्यवस्था करो। इस समस्या का सबसे जरूरी पक्ष नागरिकों की जागरूकता से जुड़ा है। उनको संक्रमण से बचना और अपने परिवार को बचाना है तो इस उच्छिष्ट को घरेलू कचरे से अलग रखते हुए निर्धारित स्थान तक पहुंचाना होगा। हर नागरिक का सामाजिक कर्तव्य है कि वह स्वयं भी उसके निस्तारण की निगरानी का दायित्व निभाए। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली परिस्थिति छोटे शहरों और कस्बों को लेकर है। वहां न निकाय इकाइयां और न नागरिक इस सम्बन्ध में जागरूक हैं। इन सभी स्थानों में एक खतरनाक लापरवाही और बेफिक्री का माहौल देखा जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप में गांवों और कस्बों को लेकर चिंता सबसे अधिक है। ऐसे में स्थानीय नेताओं, प्रधानों और पंचों का दायित्व हो जाता है कि वे स्वयं को और समाज को सुरक्षित रखने का मानवीय कर्तव्य पूरा करें।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ज्ञान गंगा

आत्मिक प्रगति

श्रीराम शर्मा आचार्य

अध्यात्म का अर्थ है अपने आपे का विज्ञान। पदार्थ विज्ञान का, साइंस का अपना महत्त्व है। उसी के आधार पर मानवी प्रगति की सुविधा और साधनों की अनगिनत उपलब्धियां हस्तगत हो सकती हैं। और उन्हीं के सहारे मनुष्य भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है और अन्य जीवधारियों की तुलना में अधिक साधन संपन्न बना है। अध्यात्म चेतना का विज्ञान है। मनुष्य के दो भाग हैं-एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ पंच तत्त्वों से बना शरीर है और चेतन आत्मा। जड़ शरीर के लिए जड़ जगत् से साधन उपक्रम प्राप्त होते हैं और उन्हें जुटाने के लिए भौतिक विज्ञान की विद्या अपनानी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा को चेतना की प्रगति और समृद्धि के लिए चेतना विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। अध्यात्म विज्ञान, ब्रह्मविद्या का प्रयोजन इसी महती आवश्यकता की पूर्ति करता है। अध्यात्म विज्ञान के लक्ष्य हैं-आत्मकल्याण यानी पूर्णता के परमात्मा स्तर तक पहुंचना। और इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए चार चरण निर्धारित हैं। ये हैं-

1. आत्मचिंतन, 2. आत्मसुधार, 3. आत्मनिर्माण; और 4. आत्मविकास। पहला यानी आत्मचिन्तन अर्थात् अपने चेतन, अजर अमर शुद्ध चेतन स्वरूप का मान। शरीर और मन में अपनी स्वतन्त्र एवं पृथक् सत्ता की प्रगाढ़ अनुभूति। 2. आत्मसुधार अर्थात् अपने ऊपर चढ़े हुए मल आवरण विक्षेप, कषाय-कल्मषों का निरूपण-निरीक्षण और सुसंपन्न स्थिति को विपन्नता में बदल देने वाली विकृतियों की समुचित जानकारी। 3. आत्मनिर्माण अर्थात् विकृतियों को निरस्त करके उनके स्थान पर सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की, उत्कृष्ट कर्तृत्व और आदर्श कर्त्तव्य स्थापित करने का सुनिश्चित संकल्प एवं साहसिक प्रयास जबकि चौथा चरण है आत्मविकास अर्थात् चिंतन और कर्तृत्व को लोक मंगल के लिए सत्प्रवृत्ति और संवर्धन के लिए तथा परमात्मस्तर पर विकसित होने के लिए अधिकाधिक संयम, तप, त्याग-बलिदान को सन्तोष एवं आनन्द की अनुभूति। कहना होगा कि इन चार चरणों में ही आत्मकल्याण का लक्ष्य निहित होता है, इन्हीं से प्राप्त होता है आत्मकल्याण।

आज का राशिफल

मेष व्यावसायिक योजना सफल होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

वृषभ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। धन लाभ होगा।

मिथुन पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखकर वाद विवाद की स्थिति को टाला जा सकता है। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।

कर्क आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। व्यावसायिक योजना सफल होगी। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य शिथिल होगा। विरोधी परास्त होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।

कन्या दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। खान पान में संयम रखें। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

तुला आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। प्रणय संबंधों में कटुता आ सकती है। विरोधियों का पराभव होगा।

वृश्चिक आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

धनु पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। धन लाभ की संभावना है।

मकर पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन के योग हैं। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

कुम्भ शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

मीन पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

वक्त का फैसला

जीवन अनमोल, शैक्षिक गुणवत्ता भी जरूरी

आखिरकार केंद्र सरकार ने सीबीएसई की बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय ले ही लिया। निस्संदेह, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों के लिये चिंतित थे। यह चिंता तब और बढ़ी जब खुद शिक्षा मंत्री ही प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई बैठक से पहले कोविड संक्रमण के बाद के प्रभाव के चलते एम्स में भर्ती हो गये। बहरहाल, मौजूदा संकट में यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण हो गया था कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बच्चों के जीवन को अनमोल बताते हुए, परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया। यह जरूरी भी हो गया था क्योंकि इस मुद्दे पर जमकर राजनीति होने लगी थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक परीक्षा करवाने के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे। वहीं छात्रों के कुछ समूह भी परीक्षा रद्द करवाने को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे थे। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद अधिकारियों को परीक्षा परिणाम तैयार करने को लेकर निर्देश दिये। अधिकारियों से कहा गया है कि परिणाम पूर्णत- निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किये जाएं। अब केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति इससे जुड़े मानदंड तैयार करेगी। संभव है छात्रों के पिछले शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर उनका परीक्षा परिणाम तैयार किया जाये। सरकार की कोशिश होगी कि समय रहते परीक्षा परिणाम घोषित किया जाये ताकि अगले सत्र को शुरू करने में कोई व्यवधान न आये। साथ ही उच्चस्तरीय मीटिंग में यह भी तय किया गया कि यदि गत वर्ष की ही तरह कुछ छात्र परीक्षा में बैठने की इच्छा रखते हैं तो परिस्थिति सामान्य होने पर उन्हें इसका विकल्प उपलब्ध कराया जाये। यद्यपि अभी परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि का जिक्र नहीं किया गया है। दरअसल, सरकार का कहना है कि कोरोना संकट से व्याप्त अनिश्चितता और इससे जुड़े सभी पक्षों से फीडबैक लेने के बाद ही यह निर्णय लिया गया कि इस बार बारहवीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जायेंगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों ने इस मुद्दे पर मंथन किया था। उसके उपरांत भी रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की राय ली गई थी; जिसमें सभी विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें परीक्षा के ऑनलाइन विकल्प, परीक्षा विद्यार्थियों के स्कूल में ही कराने, परीक्षा केंद्र बढ़ाने तथा परीक्षा की अवधि को कम करने जैसे विकल्पों पर विचार किया गया था। जबकि कुछ पक्षों का मानना था कि बिना वैक्सीन के परीक्षाओं का आयोजन नहीं करना चाहिए। बहरहाल, अब सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने के बाद आईसीएसई ने भी बारहवीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी है। उम्मीद है कि राज्यों के बोर्ड भी इसी तरह के निर्णय लेंगे। कोशिश यही है कि कोरोना संकट के कारण यह दूसरा सत्र भी बाधित न हो। बहरहाल, इस संकट के अन्य विकल्पों से जुड़ी कई समस्याएं सामने आ रही थीं। यदि परीक्षा ऑनलाइन करायी जाती तो उसमें नकल होने की संभावना बढ़ सकती थी। यदि ऑफ वक्त का फैसला जीवन अनमोल, शैक्षिक गुणवत्ता भी जरूरी आखिरकार केंद्र सरकार ने सीबीएसई की बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय ले ही लिया। निस्संदेह, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों के लिये चिंतित थे। यह चिंता तब और बढ़ी जब खुद शिक्षा मंत्री ही प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई बैठक से पहले कोविड संक्रमण के बाद के प्रभाव के चलते एम्स में भर्ती हो गये। बहरहाल, मौजूदा संकट में यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण हो गया था कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बच्चों के जीवन को अनमोल बताते हुए, परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया। यह जरूरी भी हो गया था क्योंकि इस मुद्दे पर जमकर राजनीति होने लगी थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक परीक्षा करवाने के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे। वहीं छात्रों के कुछ समूह भी परीक्षा रद्द करवाने को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे थे। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद अधिकारियों को परीक्षा परिणाम तैयार करने को लेकर निर्देश दिये। अधिकारियों से कहा गया है कि परिणाम पूर्णत- निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किये जाएं। अब केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति इससे जुड़े मानदंड तैयार करेगी। संभव है छात्रों के पिछले शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर उनका परीक्षा परिणाम तैयार किया जाये। सरकार की कोशिश होगी कि समय रहते परीक्षा परिणाम घोषित किया जाये ताकि अगले सत्र को शुरू करने में कोई व्यवधान न आये। साथ ही उच्चस्तरीय मीटिंग में यह भी तय किया गया कि यदि गत वर्ष की ही तरह कुछ छात्र परीक्षा में बैठने की इच्छा रखते हैं तो परिस्थिति सामान्य होने पर उन्हें इसका विकल्प उपलब्ध कराया जाये। यद्यपि अभी परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि का जिक्र नहीं किया गया है। दरअसल, सरकार का कहना है कि कोरोना संकट से व्याप्त अनिश्चितता और इससे जुड़े सभी पक्षों से फीडबैक लेने के बाद ही यह निर्णय लिया गया कि इस बार बारहवीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जायेंगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों ने इस मुद्दे पर मंथन किया था। उसके उपरांत भी रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की राय ली गई थी; जिसमें सभी विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें परीक्षा के ऑनलाइन विकल्प, परीक्षा विद्यार्थियों के स्कूल में ही कराने, परीक्षा केंद्र बढ़ाने तथा परीक्षा की अवधि को कम करने जैसे विकल्पों पर विचार किया गया था। जबकि कुछ पक्षों का मानना था कि बिना वैक्सीन के परीक्षाओं का आयोजन नहीं करना चाहिए। बहरहाल, अब सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने के बाद आईसीएसई ने भी बारहवीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी है। उम्मीद है कि राज्यों के बोर्ड भी इसी तरह के निर्णय लेंगे। कोशिश यही है कि कोरोना संकट के कारण यह दूसरा सत्र भी बाधित न हो। बहरहाल, इस संकट के अन्य विकल्पों से जुड़ी कई समस्याएं सामने आ रही थीं। यदि परीक्षा ऑनलाइन करायी जाती तो उसमें नकल होने की संभावना बढ़ सकती थी। यदि ऑफ लाइन करायी जाती तो अभिभावकों की चिंता वाजिब थी। डर था कि कहीं उनके घर के बड़े-बुजुर्ग संक्रमित न हो जायें। लेकिन इस समाधान का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि जो बच्चे टॉपर होने के लिये साल भर कड़ी मेहनत करते रहे, उन्हें इस फैसले से निराशा जरूर हुई होगी। दरअसल, आगे उच्च शिक्षा में बारहवीं की परीक्षा के ऊंचे स्कोर की दरकार होती है। सभी जगह इन नंबरों का महत्व होता है। इस फैसले से अच्छे अंक लाने की उम्मीद कर रहे मेधावी छात्र-छात्राओं को निराश होना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि छात्रों का एक साल खराब होने से बच जायेगा। साथ ही यह भी कि अगला सत्र शुरू करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही स्कूल-कॉलेजों का वातावरण जल्दी से जल्दी सामान्य हो, यह भी उम्मीद रखनी चाहिए। लाइन करायी जाती तो अभिभावकों की चिंता वाजिब थी। डर था कि कहीं उनके घर के बड़े-बुजुर्ग संक्रमित न हो जायें।

संक्रामक रोगों को आम तौर पर लोग संजीदगी से नहीं लेते। भारत में ज्यादातर लोग मुंहासों के इलाज के लिए या तो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं या उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास जा कर इलाज कराते हैं। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि मुंहासे पैदा करने वाला बैक्टीरिया एमआरएसए जानलेवा भी हो सकता है।

जानलेवा बैक्टीरिया एमआरएसए

मुंहासे पैदा करने वाला मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफीलोकोकस ऑरेउस या एमआरएसए एक ऐसा बैक्टीरिया है. जो आम तौर पर त्वचा पर आक्रमण करता है। अमेरिका में ज्यादातर त्वचा के रोग इसी विषाणु के कारण होते हैं। मुंहासों तक तो इन पर काबू कर लिया जाता है, लेकिन अगर यह किसी चोट द्वारा खून के अंदर पहुंच जाएं, तो यह शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। खास तौर से ऑपरेशन के दौरान अगर ध्यान न दिया जाए तो यह पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैला सकता है।

एंटी बायोटिक का असर नहीं

एमआरएसए को सबसे पहली बार 1961 में खोजा गया था। इससे छुटकारा पाने के लिए एंटी बायोटिक का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन इतने वर्षों में इन विषाणुओं ने खुद को इन दवाइयों के हिसाब से ढाल लिया है। मेथिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफीलोकोकस ऑरेउस या एमआरएसए पेनिसिलिन, ओक्ससिलिन जैसे ज्यादातर एंटी बायोटिक अब इन पर काम करने में विफल रहते हैं। वैज्ञानिक अब नए एंटी बायोटिक बनाने में लगे हैं।

यूरोप में लाखों बीमार

यूरोप में हर साल चालीस लाख से अधिक लोग अस्पतालों में इन्हीं एमआरएसए विषाणुओं का शिकार होते हैं। इनमें से 35,000 जर्मनी में हैं। एक अध्ययन के अनुसार यूरोप में हर साल 37,000 लोग इसलिए अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि वे अस्पताल में आकर बीमार पड़ते हैं और समय रहते उनका सही इलाज नहीं हो पाता। यूरोपीय संघ कोशिश कर रहा है कि अस्पतालों में साफ-सफाई के मापदंड अब और भी सख्त कर दिए जाएं।

मरीज की पहचान जरूरी

जर्मन सोसाइटी फॉर हॉस्पिटल हाइजीन चाहता है कि जर्मनी के हर अस्पताल में मरीज को भर्ती करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच कर ली जाए कि कहीं वह अपने साथ इस कीटाणु को तो नहीं लाया है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है, ताकि मरीज की पहचान कर ली जाए और उसे बाकी मरीजों से अलग रखा जाए। जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड में 25 प्रतिशत मरीजों में यह कीटाणु पाया गया। स्पेन और तुर्की जैसे अन्य दक्षिण यूरोपीय देशों में हालात और भी खराब हैं। वहां 50 प्रतिशत मरीज इस विषाणु से संक्रमित हैं।

एमआरएसए का बढ़ता खतरा

पिछले वर्षों में एमआरएसए के केस इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अब इसे कामकाज संबंधी बीमारी के रूप में देखा जा रहा है। जर्मन सोसाइटी फॉर हॉस्पिटल हाइजीन के अनुसार जर्मनी में 80 प्रतिशत अस्पतालों में एमआरएसए का खतरा है। इन अस्पतालों से कड़े रूप से यह कहा जा रहा है कि जो लोग साल में एक से ज्यादा बार अस्पताल में भर्ती हो रहे हों, उनकी पूरी जांच की जाए।

क्या आप जानते हैं?

क्या है डीप वैन थ्रोमयोसिस यानी 'डी वी टी'? लम्बी दूरी की थकाऊ उड़ान की कीमत अकसर पैरों और हमारी जंघाओं को चुकानी पड़ती है।

लक्षण

लम्बी दूरी उड़ान के दौरान काल्फ जैसी डीप वैन्स (निचली शिराओं में) खून का थक्का बनने लगता है। साथ में बेहद का दर्द और इन्फ्लेमेशन होने लगता है। बस यही है 'डीप वैन थ्रोम -योसिस' के लक्षण।

समाधान

डी वी टी का समाधान भी सीधा सरल है। हर एक घंटे के बाद प्लेन में एक सिरे से दूसरे तक टहलिए । पैर लटकाकर बैठे मत रहिए। खूब पानी पीजिए (हाई -डरै -टिड रखिये शरीर को) हो सके तो किसी भी प्रकार पैरों को एलीवेटिड रखिए । वैसे आप को बता दें कि आजकल फ्लाइट के दौरान पहने जाने वाले विशेष मौजे (सॉक्स)भी उपलब्ध हैं ।

यह फ्लाईट सॉक्स खास तौर पर डिजाइन किए गए कम्प्रेशन होजरी से तैयार किये जाते हैं। ये रक्त प्रवाह को पैरों की और मोड़ कर दिल तक ले जाते हैं। यह पैरों पर इस तरह से दबाव (प्रेशर) डालते हैं, जिससे दर्द घुटनों से पैरों के टखनों (एंकल) की ओर मुड़ जाता है।

हाउस वाइफ रीता आजकल बहुत चिंतित रहने लगी है। दरअसल महीने मे यह तीसरी बार है की वह अपने 6 वर्षीय बेटे रिंकू को स्थानीय अस्पताल मे दिखाने लाई है। रिंकू को बार बार दस्त हो रहे हैं। मात्र 4 दिन पहले ही रिंकू को इसी अस्पताल से छुट्‌टी मिली थी, तब उसे उल्टी दस्त की वजह से 2 दिन के लिए अस्पताल मे भर्ती किया गया था।

घर के बर्तन भी फैलाते हैं रोग

बाल रोग विशेषज्ञ ने रीता को बताया की रिंकू की बीमारी खाने से उत्पन्न बैक्टीरिया की वजह से हुई है। इसलिए उसे रिंकू की खानपान की आदतों के प्रति खास तौर पर चौकन्ना रहना होगा। डॉक्टर ने रीता को यह भी बताया कि अपने बच्चे को खाना देते वक्त उसे क्या करना है और क्या नहीं।

डॉक्टर द्वारा दी गई सूची को पूरा पढ़ने के बाद लगा जैसे रीता रो पड़ेगी, क्योंकि इस सूची में ऐसा कोई काम नहीं था जो उसने न किया हो। एक शिक्षित व समझदार मां के तौर पर रीता ने बहुत अच्छी तरह अपने बच्चे की सेहत व भलाई के हरसंभव कदम उठाया था।

रीता ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि रिंकू वहीं पानी पीए जो छना व उबला हुआ हो। उसने अपने बच्चे को हमेशा ताजा बना हुआ भोजना दिया। वास्तव में रीता के पति व उसकी सहेलियां उसका यह कह कर मजाक भी उड़ाते थे कि अपने बेटे के मामले में वह कुछ ज्यादा ही हाइजीनिक है। रीता ने बहुत सोचा, लेकिन फिर भी वह उस कारण को नहीं ढूंढ़ पाई, जिस वजह से उसके बेटे को बार बार संक्रमण हो रहा था।

उदाहरण मात्र है

रीता तो मात्र एक ही उदाहरण है। हमारे देश मे ऐसी हजारों माताएं हैं जो उस कारण को खोज रही हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे व परिवार के अन्य सदस्य बार बार बीमार पड़ते हैं। किंतु लगातार प्रयासों के बावजूद भी वे इन संक्रामक बीमारियों को अपने घर से दूर नहीं रख पा रही हैं।

वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुसार

जब हम भोजन की साफ-सफाई के बारे में बात करते हैं तो बर्तनों का जिक्र शायद ही कभी आता हो। वास्तव में बर्तन भोजन संबंधी स्वच्छता का सबसे अहम हिस्सा हैं, क्योंकि बर्तनों में ही खाना पकाया, परोसा और ले जाया जाता है। जिन बर्तनों को ठीक से धोया नहीं जाता, उनमें ऐसे जीवाणु पनप जाते हैं, जो रोगकारक होते हैं और ऐसे बर्तनों से बीमारी फैल सकती है।''

तो क्या है इसका हल?

सर्वश्रेष्ठ तरीका तो यही है कि बर्तनों को रोगाणुओं से मुक्त किया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सलाह दी जाती है कि बर्तनों को धोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में जीवाणुनाशक एजेंट होना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि बर्तन धोने के लिए जो रासायनिक एजेंट इस्तेमाल किए जाएं वे सुरक्षित हों और उनसे किसी किस्म का नुकसान न हो। साइक्लोजैन ऐसा रोगाणुरोधी एजेंट हैं, जो इस उद्देश्य को पूरा करते हैं।

उद्देश्य को पूरा करते हैं साइक्लोजैन

साइक्लोजैन मानव इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं और ये बर्तनों से 85 प्रतिशत बैक्टीरिया को साफ करने में सक्षम हैं। ये रसायन बैक्टीरिया को धो डालते हैं और लगभग 8 घंटों तक उन्हें फिर से पनपने से भी रोकते हैं। इस वक्त भारतीय बाजारों में कई ब्रांड नामों से 'डिश वॉश' फॉर्मूला उपलब्ध हैं, जिसमें साइक्लोजैन मौजूद हैं।

अनदेखा कर देते हैं अहम पहलू

- साफ-सफाई के सभी मानकों का पालन करने पर भी हम में से अधिकतर लोग भोजन दूषित होने के सबसे अहम् पहलू को अनदेखा कर देते हैं- वे बर्तन जिनमें हम खाना पकाते, रखते और खाते हैं।
- आम तौर पर प्लेटें और टिफिन को सिर्फ पानी से धो लिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि नल से आने वाला पानी रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को लिए होता है।
- भले ही आप दो-तीन बार पानी को छानें या उबालें या फिर गर्मागर्म खाना बना कर परोसें; लेकिन आपकी इन कोशिशों पर पानी फिर जाएगा, अगर यह खाना-पानी ऐसे बर्तनों में परोसा जाए, जिन्हें रोगाणुओं से मुक्त नही किया गया है।
- गिलास, कटोरी, थाली, टिफिन आदि में मौजूद बैक्टीरिया भोजन व पानी में बड़ी तेजी से मिल जाते हैं। एक बार भोजन या पानी दूषित हो गए तो फिर वे हमेशा के लिए दूषित ही रहेंगे।

देश में आए कोरोना संकट के चलते इस साल मुकेश अंबानी ने नहीं ली अपनी सैलरी

बिजनेस डेस्क।

देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कोई वेतन नहीं लिया। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते व्यापार और अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के कारण स्वेच्छा से अपना पारिश्रमिक छोड़ दिया। कई साल से मुकेश अंबानी सालाना 15 करोड़ रुपये की सैलरी ले रहे थे।

2020-21 के लिए अंबानी का पारिश्रमिक शून्य

रिलायंस की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंबानी का पारिश्रमिक ''शून्य'' था। उन्होंने इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी से 15 करोड़ रुपये का वेतन प्राप्त किया, जो पिछले 15 वर्षों से इसी स्तर पर बना हुआ था। अंबानी के चचेरे भाई निखिल और हिताल मेसवानी का पारिश्रमिक 24 करोड़ रुपये पर बरकरार रहा, लेकिन इस बार इसमें 17.28 करोड़ रुपये का कमीशन शामिल है।

इन लागों के पारिश्रमिक में हुई बढ़ोतरी

कार्यकारी निदेशक पी एम एस प्रसाद और पवन कुमार कपिल के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी हुई। प्रसाद को 2020-21 में 11.99 करोड़ रुपये मिले। ये आंकड़ा इससे पिछले वर्ष में 11.15 करोड़ रुपये था। इसी तरह कपिल का पारिश्रमिक 4.04 करोड़ रुपये से बढ़कर 4.24 करोड़ रुपये हो गया। अंबानी की पत्नी नीता, जो कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं, को प्रत्येक बैठक के लिए आठ लाख रुपये और 1.65 करोड़ रुपये का कमीशन मिला। इस दौरान सभी स्वतंत्र निदेशकों को 1.65 करोड़ रुपये का कमीशन और 36 लाख रुपये तक बैठक शुल्क मिला।

वेदांता कमीशन ने की ऑक्सीजन सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत

चेन्नई।

वेदांता लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उनके द्वारा तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में अपने कॉपर स्मेल्टर प्लांट स्टरलाइट कॉपर में ऑक्सीजन सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट चालू किया है। वेदांता के मुताबिक, 11 करोड़ रुपये के इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 400 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरने की है। वेदांता ने कहा, अब तक हमारी टेक्नोलॉजी लिक्विड ऑक्सीजन के उत्पादन पर ही सिर्फ केंद्रित थी, लेकिन विदेशी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं ने हमें गैसीय ऑक्सीजन पर भी अपनी पकड़ जमाने में मदद की है, जिसे अब तक एक उपोत्पाद के रूप में बाहर निकाला जा रहा है। स्टरलाइट कॉपर में प्रति दिन (टीपीडी) के हिसाब से 1,050 टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जिसमें 200 टीपीडी तरल ऑक्सीजन होगी और शेष गैसीय रूप में है। कंपनी ने पहले कहा था कि उसके पास विभिन्न अस्पतालों में 200-250 टीपीडी मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा है। चिकित्सा उपयोग के लिए इकाई की शेष क्षमता का उपयोग करने को लेकर वेदांता ने पहले कहा था कि उनके द्वारा राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 4.5 बार प्रेशर पर गैसीय रूप में उपलब्ध 800 टीपीडी ऑक्सीजन के परिवहन के लिए व्यावसायिक भागीदारों को तलाशा जा रहा था। वेदांता ने हाल ही में स्टरलाइट कॉपर में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया था, ताकि देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रसार के चलते अस्पतालों को इसकी आपूर्ति कराई जा सके।

माइक्रोसॉफ्ट 24 जून को विंडोज की अगली पीढ़ी का प्रदर्शन करेगा

नई दिल्ली।

माइक्रोसॉफ्ट ने खुलासा किया है कि वह 24 जून को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगली पीढ़ी का प्रदर्शन करेगा। एक मीडिया आमंत्रण के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और मुख्य उत्पाद अधिकारी पैनोस पानाय नया विंडोज अनुभव पेश करेंगे। हाल ही में संपन्न बिल्ड डेवलपर सम्मेलन के दौरान, नडेला ने विंडोज की अगली पीढ़ी पर प्रकाश डाला था।

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने 25 मई को अपने मुख्य भाषण के दौरान कहा था, जल्द ही हम डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए अधिक से अधिक आर्थिक अवसरों को अनलॉक करने के लिए पिछले दशक के विंडोज के सबसे महत्वपूर्ण अपडेटों में से एक को साझा करेंगे। मैं पिछले कई महीनों से इसे स्वयं होस्ट कर रहा हूं, और मैं अविश्वसनीय रूप से अगले पीढ़ी के विंडोज को लेकर उत्साहित हूं। उन्होंने कहा था, आपसे हमारा वादा यह है, हम आज हर विंडोज डेवलपर के लिए और अधिक अवसर पैदा करेंगे और प्रत्येक निर्माता का स्वागत करेंगे जो एप्लिकेशन बनाने और वितरित करने और मुद्रीकरण करने के लिए सबसे नवीन, नए, खुले मंच की तलाश में है। हम बहुत जल्द इस बारे में और अधिक साझा करने के लिए तत्पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी पुष्टि की है कि वह एक लाइटवेट और सिप्लीफाइड विंडोज 10 एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जारी नहीं करेगा।

नियोजेन केमिकल्स का कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद शानदार वित्तीय प्रदर्शन

नियोजेन केमिकल्स लिमिटेड (नियोजेन) का वित्तीय प्रदर्शन पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही और 31 मार्च को खत्म हुए पूरे साल के दौरान उत्साहजनक रहा है। वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही के दौरान जहां कंपनी को 93 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, वहीं पूरे वर्ष के लिए कंपनी ने 336 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इस आधार पर देखा जाए तो चौथी तिमाही में कंपनी के राजस्व में पिछले वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 13त्न और वित्त वर्ष 21 के दौरान कंपनी के राजस्व में 10त्न का इजाफा हुआ। प्रमुख उत्पादों की जबरदस्त मांग के कारण कंपनी के राजस्व में शानदार इजाफा देखने को मिला। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लगाए स्थानीय स्तरों पर लगाए प्रतिबंधों और पिछले साल दो महीनों के देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद कंपनी यह प्रदर्शन हासिल करने में कामयाब रही है। बेहतर परिचालन और प्राप्ति लाभ के कारण कंपनी का एबिटा (ईबीआइटीडीए) प्रदर्शन शानदार रहा क्योंकि सभी संयंत्र उपयुक्त स्तरों पर संचालित हो रहे थे। कोविड—19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण अतिरिक्त लागतों के बावजूद कंपनी ने सकारात्मक प्रदर्शन किया।

वित्त वर्ष 20 की चौथी तिमाही के 7 करोड़ रुपये के मुकाबले समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी का कर पश्चा त् मुनाफा (पीएटी) 9 करोड़ रुपये रहा। वहीं वित्त वर्ष 21 के लिए कर पश्चोात् मुनाफा 31 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 9त्न अधिक है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का पीएटी 29 करोड़ रुपये रहा था। पीएटी में आई तेजी की वजह बेहतर परिचालन क्षमता और राजस्व में आई तेजी रही। पूंजीगत खर्च से जुड़ा अधिक अवमूल्यन और वित्त लागत एवं कर्मचारी लागत की वजह से वृद्धि की गति में कमी आई। वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही के दौरान प्रति शेयर आय बढ़कर 4 रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3.15 रुपये रही थी।

पिछले वित्त वर्ष 21 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 21 के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते नियोजेन केमिकल्सत के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हरिदास कनानी ने कहा : 'एक ऐसे वर्ष के दौरान जो दुनिया भर में लोगों और व्यवसायों के लिए सबसे कठिन स्मृतियों में से एक रहा है, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने अपनी वृद्धि की गति को पहले बताए गए दृष्टिकोण के अनुरूप बनाए रखा है। क्षमता बाधाओं के बावजूद वित्त वर्ष 2021 के दौरान हमारे राजस्व में 10त्न की वृद्धि हुई है, मार्जिन को 19.1त्न तक बढ़ाया है और आपूर्ति श्रृंखला क्षमता को बनाए रखते हुए सभी प्रमुख अंतिम उपभोक्ता उद्योगों में मांग को बढ़ाकर मुनाफे में 9% की वृद्धि हासिल की है। यह प्रदर्शन पूरे साल भर में देश भर में लगाए गए कई व्यापक/स्थानीय प्रतिबंधों के दौरान हासिल किया गया है।'

न्यायालय ने टीका खरीद के लिये 35,000 करोड़ रुपये के कोष में से खर्च राशि का ब्योरा मांगा

नयी दिल्ली,

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से मौजूदा उदारीकृत टीकाकरण नीति के तहत 2021-22 के बजट में कोविड-19 टीका खरीद को लेकर निर्धारित 35,000 करोड़ रुपये के कोष में से खर्च की गयी राशि के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने यह भी पूछा कि आखिर कोष का उपयोग 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण पर क्यों नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने केंद्र की उदारीकृत टीकाकरण नीति पर भी गंभीर सवाल उठाए। यह नीति राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और निजी अस्पतालों को देश में सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी (सीडीएल) द्वारा मंजूर मासिक खुराक में से 50 प्रतिशत खुराक पूर्व-निर्धारित कीमत पर खरीदने की अनुमति देती है। न्यायालय ने कहा कि यदि केंद्र की एकाधिकारवादी खरीदार की स्थिति विनिर्माताओं से बहुत कम दर पर टीके प्राप्त करने का एकमात्र कारण है, तो ऐसे में अदालत के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौजूदा उदारीकृत टीकाकरण नीति की युक्तिसंगतता की जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विशेष रूप से वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर गंभीर बोझ डाल सकती है। न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश एल एन राव और न्यायाधीश एस रवींद्र भट्ट की एक विशेष पीठ ने कहा कि केंद्र का तर्क है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उदारीकृत टीकाकरण नीति लायी गयी है। यह अधिक निजी निर्माताओं को आकर्षित करेगा और इससे अंततः कीमतों में कमी आ सकती है।पीठ ने कहा, ''प्रथम दृष्ट्या, दो टीका विनिर्माताओं के साथ बातचीत को लेकर गुंजाइश केवल कीमत और मात्रा थी। जबकि दोनों ही केंद्र सरकार द्वारा पहले से तय किए गए हैं। ऐसे में प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च कीमत को लेकर भारत सरकार का जो तर्क है, उसको लेकर गंभीर संदेह पैदा होता है।'' न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार का तर्क है कि बड़े स्तर पर खरीद ऑर्डर की उसकी क्षमता से टीके की कीमतें कम हुई।

सेबी ने यूपीआई व्यवस्था के जरिये आईपीओ प्रक्रिया के लिये एसमएस एलर्ट के लिये और समय दिया

नयी दिल्ली,

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को आईपीओ के दौरान आवेदन किये गये शेयरों और आवंटित शेयरों को लेकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के तहत एसमएस एलर्ट से संबंधित दिशानिर्देश के क्रियान्वयन को लेकर और समय दे दिया। साथ ही यूपीआई प्रणाली के जरिये आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के संदर्भ में स्वचालित वेब पोर्टल स्थापित करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गयी है। संबंधित पक्षों ने नियामक से संपर्क कर कोविड महामारी के कारण अनिश्चितता का हवाला देते हुए प्रणाली में बदलाव को लेकर अतिरिक्त समय मांगा था। सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि स्वचालित वेब पोर्टल के लिये नये विधान अब एक अक्टूबर, 2021 से अस्तित्व में आएंगे जबकि एसएमएस एलर्ट से संबंधित नियम एक जनवरी, 2022 से प्रभाव में आएंगे। पूर्व में नई व्यवस्था को एक मई, 2021 से बाजार में आने वाले आईपीओ के लिये प्रभाव में आना था।

स्वदेशी 5 जी नेटवर्क सेवाओं के विकास और उसे पेश करने की प्रक्रिया को तेज कर रही है जियो

नयी दिल्ली, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्वदेशी तरीके से विकसित अगली पीढ़ी की 5जी सेवाएं पेश करने की प्रक्रिया को गति दे रही है। भारत के वैश्विक डिजिटल क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने का जिक्र करते हुये यह कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो ने अगले 30 करोड़ मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा उपयोगकर्ताओं, जियो फाइबर का इस्तेमाल करने वाले पांच करोड़ घरों और पांच करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यापार इकाइयों के लिए पर्याप्त नेटवर्क क्षमता का निर्माण किया है। कंपनी के चैयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने रिपोर्ट में कहा कि क्वालकॉम और जियो ने जियो भारत में 5जी निदान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जियो 5जी निदान पर एक जीबीपीएस स्पीड का महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जियो और क्वालकॉम ने जियो प्लेटफॉर्म्स की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी रेडिसिस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक मुक्त और अंतर-संचालित इंटरफेस-अनुकूलन आधारित 5जी निदान का विकास किया है जो वर्चुअलाइज्ड आरएएन (वीआरएएन) से लैस है। यह भारत में स्वदेशी 5जी नेटवर्क ढांचे और सेवाओं के विकास और उसे पेश करने की प्रक्रिया को तेज कर देगा।

रोस्सारी बायोटेक 421 करोड़ रुपए में करेगी यूनिटॉप केमिकल्स का अधिग्रहण

मुंबई, स्पेशलिटी-केमिकल्स निर्माता रोस्सारी बायोटेक ने बुधवार को यूनिटॉप केमिकल्स का 421 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा की। रोस्सारी ने एक बयान में कहा कि वह यूनिटॉप केमिकल्स की 100 प्रतिशत इक्विटी कैपिटल का अधिग्रहण करेगी। यूनिटॉप केमिकल्स सर्फेक्टेंट, इमल्सिफायर और स्पेशलिटी केमिकल्स की आपूर्तिकर्ता कंपनी है। कंपनी ने कहा कि 65 प्रतिशत इक्विटी शेयर का अधिग्रहण लेन-देन पूरा होने पर किया जाएगा जबकि शेष 35 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण अगले दो साल में पूरा होगा। कंपनी की 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिये 421 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इस अधिग्रहण के साथ कंपनी की उत्पाद श्रेणी का विस्तार होगा। रोस्सारी बायोटेक के प्रवर्तक एवं कार्यकारी चैयरमैन एडवर्ड मेनेजेस और प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक सुनील चारी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्हें रोस्सारी की वृद्धि रफ्तार बढ़ाने को लेकर खुशी है। उन्होंने कहा कि यूनिटॉप केमिकल्स कंपनी के कारोबार के लिहाज से उपयुक्त है और अपने साथ वृद्धि के और आयाम लेकर आएगी।

भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में मई में आई कमीः पीएमआई

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते एक बार फिर लॉकडाउन और प्रतिबंध लागू करने के चलते सेवा क्षेत्र की गतिविधियां आठ महीनों में पहली बार संकुचित हुई। एक मासिक सर्वेक्षण में गुरुवार को यह बात कही गई। मौसमी रूप से समायोजित भारत सेवा व्यवसाय गतिविधि सूचकांक मई में गिरकर 46.4 पर आ गया, जो अप्रैल में 54 पर था। पीएमआई की भाषा में 50 से ऊपर के अंक का अर्थ है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, जबकि 50 से नीचे का स्कोर संकुचन को दर्शाता है। आईएचएस मार्किट की प्रधान अर्थशास्त्री पोलियाना डी लीमा ने कहा कि संकट की तीव्रता और इसके चलते लागू प्रतिबंधों ने भारतीय सेवा क्षेत्र के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग को कम कर दिया। कुल बिक्री आठ महीनों में पहली बार घटी, जबकि बाहरी ऑर्डर में गिरावट पिछले साल नवंबर के बाद सबसे अधिक थी। पोर्ट के मुताबिक भारतीय सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मांग भी सुस्त रही और नए निर्यात कारोबार में छह महीने में सबसे तेज दर से गिरावट हुई। लीमा ने कहा कि इसका असर सेवा क्षेत्र में रोजगार की स्थिति पर भी पड़ा और बिक्री में कमी के चलते सेवा कंपनियों को मई के दौरान फिर से कार्यबल संख्या में कटौती के लिए मजबूर होना पड़ा।

2025 तक भारत में होंगे 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स

नेशनल डेस्कः इंटरनेट एडं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई)- कांतार क्यूब की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2025 तक लगभग 45 प्रतिशत बढ़कर 90 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक शहरी केंद्रों की तुलना में ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक हो सकती है, जो देश में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत को दर्शाता है। पिछले साल तक यह संख्या 62.20 करोड तक थी। रिपोर्ट में कहा गया, ''2025 तक, शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक होगी। इसे देखते हुए इस उभरती हुई जनसांख्यिकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की जरूरत है। कांतार के कार्यकारी उपाध्यक्ष विश्वप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में आंचलिक क्षेत्र के कारण ध्वनि एवं वीडियो डिजिटल इकोसिस्टम में बहुत बड़े बदलाव होंगे। रिपोर्ट बताती है कि भले ही शहरी भारत में इंटरनेट की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में दो गुने से अधिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की संख्या साल-दर-साल तेजी से बढ़ रही है।

मुश्किल दौर में रिलायंस ने खोले मदद के दरवाजे, कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों का खर्चा उठाएगी कंपनी

- कर्मचारी के बच्चों के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तक का खर्च उठाएगी कंपनी
- मृतक कर्मचारी के नॉमिनी को आखिरी बार मिली सैलरी जितनी मिलेगी धनराशि
- परिवार के अस्पताल में भर्ती होने का पूरा खर्च उठाएगी रिलायंस
- कोरोना मरीज पूरी तरह ठीक होने तक ले सकते हैं कोविड-19 लीव

बिजनेस डेस्क।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने संकट की इस घड़ी में कर्मचारियों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने 'रिलायंस फैमिली सपोर्ट एंड वेलफेयर स्कीम' की घोषणा करते हुए कहा कि **RIL** कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को अगले 5 साल तक सैलरी देती रहेगी।

- कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को 5 साल तक मिलेगी सैलरी
- मुकेश अंबानी ने खत लिखकर किया ऐलान

इसके अलावा कंपनी बच्चों के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस, हॉस्टल और किताबों का पूरा खर्च उठाएगी। मुकेश अंबानी ने एक खत के जरिए इसकी सूचन दी। उन्होंने लिखा कि प्रिय साथियो, कोविड-19 महामारी हमारे सामने हाल के इतिहास में सबसे भयावह अनुभव लेकर सामने आई है। हममें से कुछ लोग अपने अमूल्य सहयोगियों, पारिवारिक सदस्यों और प्रियजनों की दुखद मृत्यु से उपजे हालात का सामना कर रहे हैं।

परिवारों के दुख के वक्त में रिलायंस खड़ा है साथः अंबानी

खत में आगे लिखा कि कोरोना के इस दौर में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के दुख के वक्त में रिलायंस पूरी ताकत से साथ खड़ा है. रिलायंस परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपके साथ वादे को पूरा करने के लिए हम रिलायंस फैमिली सपोर्ट एंड वेलफेयर स्कीम की घोषणा कर रही है। किसी भी मृतक कर्मचारी के नॉमिनी को आखिरी बार मिली सैलरी जितनी धनराशि अगले पांच साल तक दी जाएगी। बच्चों को भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, किताबें मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी।

कोरोना मरीज पूरी तरह ठीक होने तक ले सकते हैं कोविड-19 लीव

इसके साथ ही अंबानी ने बताया कि जीवनसाथी, माता-पिता, बच्चों (ग्रेजुएशन तक) के अस्पताल में भर्ती होने का पूरा खर्च रिलायंस द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जो कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड की चपेट में है तो वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक होने तक कोविड-19 लीव ले सकते हैं।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

52 हजार के ऊपर निकला सेंसेक्स, निफ्टी 114 अंक ऊपर आया

टाइटन एचडीएफसी बैंक, एल एंड टी के शेयरों से आया उछाल

मुम्बई ।

घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुआ। दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बाद भी एचडीएफसी बैंक, एल एंड टी और टाइटन जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में आये उछाल से बाजार ऊपर आया है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 382.95 अंक करीब 0.70 फीसदी बढ़त के साथ 52,232.43 अंक पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 114.15 अंक यानी 0.73 फीसदी ऊपर आकर 15,690.35 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों में सबसे ज्यादा लाभ में टाइटन रही। इसके शेयरों में करीब 7 फीसदी की तेजी आयी। इसके अलावा ओएनजीसी, एल एंड टी, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी तेजी रही जबकि इंडसइंड बैंक, पावरग्रिड, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और डा. रेड्डीज आदि के शेयरों में गिरावट रही। जानकारों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह बने होने से यह बढ़त पर है।

इसके साथ ही वित्तीय सेवा कंपनियों के शेयरों में तेजी से बाजार को समर्थन मिला। रियल्टी, उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) और धातु कंपनियों के शेयरों के ऊपर आने से भी बाजार को सहारा मिला हालांकि आईटी, दवा और वाहन कंपनियों के शेयरों पर कुछ दबाव रहा। मध्यम और छोटी कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन अच्छा बना हुआ है। कारोबार के अंत में सबसे अधिक टाइटन का शेयर 6.69 फीसदी तक उछला।

इसके बाद ओएनजीसी, एलएंडटी, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी, नेस्ले इंडिया, इंफोसिस, एनटीपीसी, एसबीआई, एयरटेल, टीसीएस, रिलायंस, मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, हिन्दुस्तान युनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट और आईटीसी के शेयरों में तेजी देखी गई जबकि इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो एमबीएम, डाक्टर रेड्डी, एचसीएल टेक, सनफार्मा और बजाज फिनसर्व के शेयर में गिरावट रही।

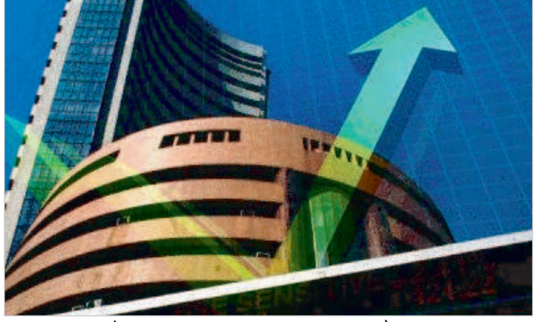

मुझे टी 20 क्रिकेट पसंद है : गावस्कर

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का कहना है कि उन्हें अपने समय के खिलाड़ियों की तुलना में टी 20 प्रारूप ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें ज्यादा एक्शन है। पूर्व समय के कई खिलाड़ी टी20 प्रारूप की आलोचना कर चुके हैं और इनका मानना है कि टी20 क्रिकेट के कारण टेस्ट क्रिकेट अपनी प्रासंगिकता खो रहा है।गावस्कर ने कहा, मुझे पता है कि कई लोग जो मेरे समय में खेलते थे वे टी20 प्रारूप से खुश नहीं है लेकिन मुझे यह पसंद है। मैं इसे इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि यह तीन घंटे का खेल है और इसमें जल्द नतीजे आ जाते हैं।उन्होंने कहा, जब कोई स्विच हिट और रिवर्स स्विप लगाता है तो मुझे बेहद पसंद आता है क्योंकि ये बेहतरीन शॉट होते हैं और इसे खेलने के लिए प्रतिभा की जरूरत है। पूर्व भारतीय कप्तान ने दक्षिण अफ्रीका के एबी डीविलियर्स को इस प्रारूप का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार दिया। गावस्कर ने कहा, डीविलियर्स जैसे बल्लेबाज हैं वह हर का शॉट खेल सकते हैं। वह दूरी में छक्का मारते हैं। जब वह शॉट लगाते हैं तो देखने लायक होता है। मुझे उन्हें बल्लेबाजी करते देखना बेहद पसंद है।

प्रधानमंत्री मोदी ने तोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 दिन के अंदर शुरू होने वाले तोक्यो ओलंपिक के लिए गुरूवार को भारत की तैयारियों की समीक्षा के लिये आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर जोर दिया कि खिलाड़ियों के टीकाकरण से लेकर ट्रेनिंग सुविधाओं तक की प्रत्येक जरूरत को शीर्ष प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। एक बयान के अनुसार मोदी ने कहा कि खेल हम सभी के दिल में हैं और देश के युवा खेलों की मजबूत संस्कृति बना रहे हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि वह भारत के ओलंपिक दल को प्रेरित करने के लिए जुलाई में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उनसे जुड़ेंगे और सभी भारतीयों की ओर से उन्हें शुभकामनायें देंगे। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाए ओलंपिक में भाग लेने वाले युवाओं के साथ होंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रत्येक खिलाड़ी के चमकने से हजारों और लोग खेलों में आने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार मोदी को बताया गया कि कुल 100 खिलाड़ियों ने 11 खेलों की स्पर्धाओं में तोक्यो ओलंपिक के लिये क्वालीफाई कर लिया है और 25 और खिलाड़ियों के क्वालीफाई करने की संभावना है। इसके अनुसार 2016 रियो डि जिनेरियो में हुए पिछले पैरालंपिक में कुल 19 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और तोक्यो पैरालंपिक के लिये 26 पैरा खिलाड़ियों ने क्वालीफाई कर लिया है और 16 और के क्वालीफाई करने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रेरित करने और उनका मनोबल बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिये 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक के दौरान भारत में उनके माता-पिता और परिवार के सदस्यों के साथ नियमित वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की जाएंगी। इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने आगामी खेलों के लिए परिचालन तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। मोदी को इसकी जानकारी भी दी गई कि कोविड-19 महामारी के दौरान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो तथा ओलंपिक कोटा जीतने के लिए अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भागीदारी और खिलाड़ियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। मोदी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ी और संभावित एथलीट तथा तोक्यो की यात्रा करने वाले सहयोगी स्टाफ और अधिकारियों का जल्द से जल्द टीकाकरण कराया जाना चाहिए।

ब्राजील करेगा कोपा अमेरिका की मेजबानी, मरकाना में होगा फाइनल

साओ पाउलो :

दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संस्था कॉनमेबोल ने कोपा अमेरिका को लेकर बनी अनिश्चितता दूर करते हुए ब्राजील को इसकी मेजबानी सौंपी है। कॉनमेबोल ने बुधवार को घोषणा की कि रियो डि जेनेरियो के ऐतिहासिक मरकाना स्टेडियम में 10 जुलाई को फाइनल खेला जाएगा जबकि इसका उदघाटन मैच ब्राजील और वेनेजुएला के बीच 13 जून को ब्राजीलिया के माने गरिन्चा स्टेडियम में खेला जाएगा। मरकाना स्टेडियम को केवल फाइनल की मेजबानी सौंपी गई है। इसी स्टेडियम में दो साल पहले ब्राजील ने पेरू को 3-1 से हराकर अपना नौवां खिताब जीता था। कोपा अमेरिका की मेजबानी पहले अर्जेंटीना और कोलंबिया को सौंपी गयी थी। अर्जेंटीना में कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण मेजबानी से हटा दिया गया था। कोलंबिया में राष्ट्रपति इवान ड्यूक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं जिससे उसे अपनी मेजबानी गंवानी पड़ी थी। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ब्राजील को मेजबानी सौंपने की भी आलोचना की है जहां कोविड-19 के कारण मृतकों की संख्या 465,000 के पार पहुंच चुकी है। टूर्नामेंट के प्रारूप के अनुसार टीमों को पांच-पांच के दो ग्रुप में बांटा गया है। अर्जेंटीना, बोलिबिया, उरूग्वे, चिली और पराग्वे को ग्रुप ए में जबकि ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्केडर और पेरू को ग्रुप बी में रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप से चोटी की चार टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। क्वार्टर फाइनल दो और तीन जुलाई को रियो डि जेनेरियो, गोइनिया और ब्राजीलिया में जबकि सेमीफाइनल रियो डि जेनेरियो और ब्राजीलिया में पांच और छह जुलाई को खेले जाएंगे।

सिंधू ने मारिन से कहा- ओलंपिक में तुम्हारी कमी खलेगी

नई दिल्ली : भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू ने बुधवार को स्पेन की कैरोलिना मारिन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि ओलंपिक खेलों में गत चैम्पियन की कमी खलेगी। मारिन को घुटने की चोट के कारण ओलंपिक से नाम वापिस लेना पड़ा है। तोक्यो ओलंपिक में पदक की सबसे प्रबल दावेदार मारिन को अभ्यास के दौरान घुटने में चोट लगी और उन्होंने मंगलवार को खेलों से नाम वापिस ले लिया। रियो ओलंपिक फाइनल में मारिन से हारी सिंधू ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा कि आपकी चोट के बारे में सुनकर दुख हुआ । उम्मीद है कि आप जल्दी स्वस्थ होकर मजबूती से वापसी करोगी। सिंधू ने कहा कि मुझे पिछले ओलंपिक याद है जब हम फाइनल खेले थे । तुम्हारे खिलाफ खेलना अच्छा लगा और इस बार कोर्ट पर तुम्हारी कमी खलेगी।

अगले सप्ताह से खेले जाएंगे PSL 6 के बचे हुए मैच, 24 जून को होगा फाइनल

स्पोर्ट्स डेस्क।

पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2021 के शेष मैच अबू धाबी में 9 से 24 जून तक खेले जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान पुरुष टीम 25 जून को यूएई से मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। पीएसएल के दौरान 6 डबल हेडर होंगे। क्वालीफायर और पहला एलिमिनेटर 21 जून को खेला खेला जाएगा। दूसरा एलिमिनेटर मैच 22 जून को और फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। मार्च में 14 मैचों के बाद कोरोना वायरस के मामले सामने आने पर टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया था। पीएसएल की बहाली 9 जून को चौथे स्थान पर काबिज लाहौर कलंदर्स और तीसरे स्थान पर काबिज इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगी। पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि 2016 में अपनी स्थापना के बाद से एचबीएल पीएसएल ने साल-दर-साल एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी लीग के रूप में उभरने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है और उन पर काबू पाया है। उन्होंने कहा, पीएसएल ब्रांड की वृद्धि और विश्वसनीयता पीसीबी के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है और मुझे खुशी है कि हमने पिछले 10 दिनों में हमारे नियंत्रण से बाहर चल रहे दबावों और बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखा है। सभी ने अथक प्रयास किया है। समाधान और आगे का रास्ता खोजा और मुझे खुशी है कि अब हम पूरे कार्यक्रम की घोषणा करने की स्थिति में हैं। वसीम खान ने कहा, पीसीबी और फ्रेंचाइजी के बीच एक आम सहमति थी कि 2021 में शेष मैचों को पूरा करना अनिवार्य था ताकि हमारे पास एचबीएल पीएसएल 7 के लिए 2022 हो। अब, उचित परिश्रम और सावधानीपूर्वक योजना के माध्यम से सभी बाधाओं को दूर करने के बाद मुझे विश्वास है कि हम सामूहिक रूप से वांछित उद्देश्य को प्राप्त किया है।

संक्षिप्त समाचार

भारतीय पुरूष और महिला क्रिकेट टीमें इंग्लैंड पहुंची, रोहित शर्मा ने शेयर की फोटो

लंदन : भारतीय पुरूष क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और इसके बाद मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट श्रृंखला के लिए गुरूवार को यहां पहुंच गई। पुरूष टीम के साथ महिला टीम भी आई है जो इंग्लैंड दौरे पर तीन वनडे और इतने ही टी20 के अलावा एक टेस्ट मैच खेलेगी जिसकी शुरूआत 16 जून से ब्रिस्टल में होगी। शीर्ष क्रम बल्लेबाज के एल राहुल ने लंदन में सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि करते हुए पीछे चार्टर्ड फ्लाइट की फोटो के साथ ट्वीट किया फ्लाइट उतर गई। दोनों टीमें अब साउथम्पटन की यात्रा करेंगी जिसमें वे अपना अनिवार्य पृथकवास पूरा करेंगी। पृथकवास पूरा करने और इसके बाद कोविड-19 जांच के बाद विराट कोहली की अगुआई वाली पुरूष टीम 18 जून से यहां विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। इसके बाद पुरूष टीम नाटिंघम में चार अगस्त से शुरू होने वाली पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए इंग्लैंड के सामने होगी। भारत कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के लिये 20 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचा है। महिला टीम का दौरा 15 जुलाई को समाप्त होगा।

गेंद से छेड़छाड़ मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सीए : साकर

मेलबर्न । गेंद से छेड़छाड़ मामला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के पूर्व गेंदबाजी कोच डेविड साकर ने कहा है कि सीए साल 2018 में गेंद से छेड़छाड़ मामले से जुड़ी अपनी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे। साकर के अनुसार तभी इस घटना से जुड़े सवाल समाप्त होंगे। कैमरन बैनक्रॉफ्ट के पिछले दिनों दिये एक बयान के बाद से ही यह मामला फिर उछल गया है। बैनक्रॉफ्ट ने कहा था कि टीम के गेंदबाजों को इस बारे में जानकारी थी हालांकि बाद मेंट पैट कमिंस सही सभी गेंदबाजों ने बैनक्रॉफ्ट की बातों को गलत बताया था। बैनक्रॉफ्ट भी बाद में अपने बयान से पलट गये थे। साकर ने कहा था कि वह भी इस घटना के लिए जवाबदेह हो सकते हैं। इस घटना के कारण बैनक्रॉफ्ट, तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वॉर्नर पर प्रतिबंध लगा था। साकर ने स्थानीय मीडिया से कहा, मुझे इसको सार्वजनिक नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता है, लेकिन सीए इस मामले को कैसे संभालना चाहता है यह उस पर निर्भर करता है। साकर से पूछा गया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) को इस रिपोर्ट को क्यों सार्वजनिक करना चाहिए, उन्होंने कहा, क्योंकि ये सवाल लगातार उठते रहेंगे और हो सकता है कि इसको सार्वजनिक करने के बाद ऐसे सवालों पर विराम लग जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। सवाल इसके बाद भी उठते रहेंगे।

सोनी सब के 'वागले की दुनिया- नई पीढ़ी नये किस्से ' की भारती आचरेकर ने कहा, ' 'इस कठिन समय में परिवार का सपोर्ट मिलना जरूरी है''

प्रतिभाशाली और सदाबहार अभिनेत्री भारती आचरेकर ने साल 1980 में अपने कॅरियर की शुरूआत बॉलीवुड की अत्यं त सराही गई फिल्मा 'अपने पराये' में एक भूमिका से की थी। इसके बाद उन्हें सीरीज और फिल्मों में कई और प्रमुख भूमिकाएं मिलीं। उन्हें श्रीमती वागले की भूमिका के लिये काफी लोकप्रियता मिली है और आज भी वह सोनी सब के 'वागले की दुनिया- नई पीढ़ी नये किस्से ' में अदाकारी करते हुए दर्शकों का दिल जीत रही हैं। इस कठिन समय में, वह परिवार के महत्वी पर जोर देने में विश्वाकस करती हैं और उनका कहना है कि यह सकारात्मकता फैलाने में मदद करता है।

इस बारे में अपने विचार रखते हुए भारती आचरेकर कहती हैं, ' 'यह शो मेरे लिये एक आशीर्वाद जैसा रहा है और मैं एक बार फिर श्रीमती राधिका वागले की भूमिका निभाने का अवसर पाकर अत्यंजत आभारी हूं। मैंने अपने कॅरियर में कई भूमिकाएं की हैं, लेकिन राधिका का रोल आज भी दर्शकों को चकित कर देता है। हमारे दर्शकों और प्रशंसकों ने मुझे और इस शो को जो प्याहर और सराहना दी है, उसके लिये मैं उनकी शुक्रगुजार हूं।' '

व्यक्ति के जीवन में परिवार के महत्वस पर जोर देते हुए, भारती आचरेकर कहती हैं, ' 'इस कठिन समय में परिवार का सहयोग लेना जरूरी है, हमारा परिवार ही हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें सहयोग देता है। इस कठिन समय में, हमारे परिवार न केवल हमारे साथ खड़े रहे हैं, बल्कि हमारे वर्कप्लेकस के लोगों ने भी साथ दिया है। अपने शो के जरिये हम जिन्द गी के उतार-चढ़ावों में परिवारों के एकजुट रहने और एक-दूसरे का सहयोग करने के महत्वे पर जोर देने की कोशिश करते हैं। इससे जिन्द गी के सफर में सकारात्मककता फैलाने में मदद मिलती है। हमारा शो इन सभी मूल्यों पर दिल से यकीन करता है और परिवार की खूबसूरती तथा महत्वं पर प्रकाश डालता है।' '

अपनी ऑन-स्क्रीन फैमिली के बारे में भारती आचरेकर ने कहा, ' 'कुछ रिश्तेा और बंधन कभी बदलते नहीं हैं। इसलिये आंजन और मेरे बीच वही केमिस्ट्री दिखायी गयी है, जिसे लोगों ने पसंद किया था। अब अंतर केवल एक बात का है कि हमारी उम्र बढ़ चुकी है और शो में हमारी शादी को 40 साल हो चुके हैं, तो यह एक बदलाव स्वाभाविक है। केमिस्ट्री और मूल्यल वही रहेंगे, लेकिन पति और पत्नीह के बीच थोड़ी नोंक-झोंक चलती रहेगी। इस तरह, किरदार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन सीनियर वागलेज की टोन और बर्ताव में थोड़ा बदलाव आया है। इस नये वर्जन का सबसे महत्व पूर्ण पहलू यह है कि तीन पीढ़ियां बड़ी हो चुकी हैं और अब मुझे दादी मां की भूमिका में देखा जा रहा है।' '

'वागले की दुनिया- नई पीढ़ी नये किस्सेत' में भारती आचरेकर को श्रीमती वागले की भूमिका में देखते रहिये, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, केवल सोनी सब पर

अपनी पहली सर्विस से संतुष्ट हैं सेरेना

पेरिस।

अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का कहना है कि वह अपनी पहली सर्विस से संतुष्ट हैं। सेरेना ने फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में रोमानिया को मिहाएला बुजारनेस्कू को 6-3, 5-7, 6-1 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई थी। सेरेना तीन बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुकी हैं और उन्होंने आखिरी बार यह टूर्नामेंट 2015 में जीता था। सेरेना ने दूसरे दौर के मुकाबले में अपनी पहली सर्विस से 75 फीसदी अंक जीते थे। सेरेना ने कहा, मुझे आज काफी अच्छा लग रहा है। मैंने सर्विस का काफी अभ्यास किया है। मुझे खुशी है कि मैंने इस मैच में बेहतर किया। उन्होंने कहा, मेरे कोच ने मुझसे कहा कि यह अच्छा है कि मैंने अभ्यास में बेहतर किया था क्योंकि इससे मैच में चीजें सही होती है। मेरे पास दूसरा सेट जीतने का अच्छा मौका था। सेरेना ने इस मैच में 26 विनर्स लगाए और 27 बेजां भूलें की जबकि मिहाएला ने 25 विनर्स और 28 बेजां भूलें की। मिहाएला ने कहा, लंबे समय से मेरा सेरेना के खिलाफ खेलने का सपना था। मुझे लगा था कि मैच अच्छा होगा। ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ खेलना जो ताकत के साथ शॉट लगाता हो, यह काफी कठिन होता है। मैच के बाद मैं निराश हो गई।

भारत के आस्ट्रेलिया दौरे से महिला क्रिकेट को मिलेगी लय : निक हॉकले

सिडनी :

कोविड-19 महामारी के कारण पुरुषों से अधिक महिला क्रिकेट को नुकसान हुआ है और क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) के सीईओ निक हॉकले ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि भारतीय टीम आगामी दौरे पर जब यहां आएगी तो एक बार फिर लय मिलेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत 19 से 24 सितंबर के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के साथ होगी जिसके बाद सितंबर से तीन अक्टूबर तक एकमात्र दिन-रात्रि टेस्ट मैच खेला जाएगा। आग्रह स्वीकार करने के लिए बीसीसीआई का आभार जताते हुए हॉकले ने कहा कि इन मैचों से महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। यूनिसेफ आस्ट्रेलिया की भारत कोविड अपील के लिए पैसा जुटाने के इरादे से 12 घंटे की लाइव गेमिंग में हिस्सा लेते हुए हॉकले ने कहा, 'खेल (महिला क्रिकेट) की प्रगति को देखना शानदार है। हम काफी भाग्यशाली रहे कि पिछले साल दुनिया भर में कोविड के प्रकोप से पहले टी20 विश्व कप का आयोजन करा पाए। और इन मैचों से दोबारा लय मिलेगी। उन्होंने कहा, 'महिला क्रिकेट को कोविड के कारण पुरुषों से अधिक नुकसान पहुंचा है। मैं भारतीय टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पृथकवास से गुजरने की जानकारी होने के बावजूद वे यात्रा के लिए राजी हो गए। यह बड़ा निवेश है। हॉकले ने कहा, 'टी20 विश्व कप के फाइनल में हार के बाद भारत पलटवार (आस्ट्रेलिया पर) की कोशिश करेगा। पिछले साल मार्च में टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत को आस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रन से हार झेलनी पड़ी थी। भारतीय महिला टीम के आस्ट्रेलिया दौरे का अंत सात से 11 अक्टूबर तक तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के साथ होगा। एडीलेड में 2006 के बाद आस्ट्रेलिया में यह भारतीय महिला टीम का पहला टेस्ट होगा। यह महिला क्रिकेट के इतिहास का दूसरा दिन-रात्रि टेस्ट होगा। पहला टेस्ट 2017 में सिडनी में आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था जो ड्रॉ रहा। यह 2014 के बाद पहली बार होगा जब भारतीय टीम एक कैलेंडर वर्ष में दो टेस्ट मैच खेलेगी। भारत को 16 जून से इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में भी एकमात्र टेस्ट खेलना है।

बायो बबल में रहना मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है : रसेल

अबु धाबी। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैरेबियाई खिलाड़ी आंद्रे रसेल का कहना है कि बायो बबल में रहने से वह मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मौजूद रसेल ने कहा कि क्वारंटीन का जीवन उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। रसेल ने जियो न्यूज से कहा, मैं किसी अन्य खिलाड़ी या कोच के बारे में नहीं कह सकता लेकिन मेरे लिए क्वारंटीन में रहना मानसिक रूप से परेशान करने वाला है क्योंकि बबल में रहने से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। उन्होंने कहा, अंत में मैं आभारी हूं कि हम खेल पा रहे हैं और हम अपना काम कर पा रहे हैं। हमारे लिए यह कठिन है लेकिन फिर भी हम इसके लिए तैयार हैं। रसेल ने कहा, मैं अपने कमरे में कुछ जगह रखना चाहता हूं जिसका इस्तेमाल कर सकूं। हालांकि मैं अभी भी कुछ व्यायाम करने की कोशिश करता हूं। बुधवार को भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने भी खिलाड़ियों पर वर्कलोड के कारण अलग-अलग दौरों के लिए अलग टीम भेजने के विचार का समर्थन किया था।

अवैध बांधकाम के निर्माण में लिंबायत जोन का प्रथम स्थान

जोनल के मार्गदर्शन के अनुसार बिल्डर करते हैं अवैध बांधकामो का निर्माण

सूरतभूमि, सूरत।

यूं तो सूरत की पहचान डायमंड और टेक्सटाइल की वजह से देश में प्रचलित है लेकिन कुछ दिनों में ही भू माफियाओं द्वारा यह शहर अवैध बांधकामों के लिए भी जाना जाएगा। कुछ दिन पहले ही लिंबायत जोन के जवाबदार अधिकारी द्वारा डिंडोली विस्तार में प्रियंका सोसाइटी के पास चल रहे अवैध कमर्शियल बांधकाम का निर्माण ध्वस्त करके लिंबायत जोन के अधिकारियों ने खूब वाहवाही लूटी लेकिन बिल्डर द्वारा कुछ ही हफ्तों बाद यह बांधकाम को फिर से पूरा कर लिया गया।

विस्तार में तो ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं की कुछ बड़े तबके के नेताओं का आशीर्वाद भी बिल्डर के साथ है हम शहर के विकास की बात करते हैं। लेकिन क्या यही विकास है सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा इस अवैध बांधकाम का डेमोलेशन किया गया।

कुछ दिन पश्चात यह बांधकाम पुनः तैयार हो गया जिससे कि स्थानिक जनता का विश्वास इन अधिकारियों पर से उठता नजर आ रहा है क्योंकि अगर यही किसी आम जनता का बांधकाम होता तो जवाबदार अधिकारी आम इंसान को दुनिया भर के कानून कायदे की बात समझा देते लेकिन एक कहावत कही गई है **बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपैया अर्थात रुपए के बल पर आप अवैध बांधकाम का निर्माण धड़ल्ले से कर सकते हैं।**

युवक ने कलेक्टर और एसपी को खत लिखकर की मांग

मोरबी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गृह राज्य गुजरात में जहां एक ओर शराबबंदी लागू है तो वहीं दूसरी ओर शराब की कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। शराबबंदी के बावजूद कई जगहों पर पुलिस की निगरानी में शराब बिक रही है। कई मामलों में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। इस बीच गुजरात के मोरबी निवासी ने जिला कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर शराब बेचने की अनुमति मांगी है।

मिल रही जानकारी के अनुसार मोरबी के लीलानगर गांव के प्रकाशनगर निवासी गौतम मकवाणा नाम के एक याचिकाकर्ता कलेक्टर और एसपी को खत लिखकर शराब बेचने की अनुमति मांगी है। अपनी अर्जी में गौतम मकवाणा ने कहा, हम पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और दैनिक काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यहां मोरबी में जमकर शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस शराब माफियों से हफ्ता लेकर शराब बेचने की अनुमति दे रही है। इसलिए मुझे भी शराब बेचने की अनुमति दी जाए। पत्र में गौतम ने आगे लिखा कि गुजरात में सिर्फ नाममात्र का शराबबंदी कानून है।

इसलिए मुझे भी शराब का धंधा शुरू करने की अनुमति दी जाए। इसके लिए सरकार के नियमानुसार जो भी पैसा देना होगा मैं देने को तैयार हूं। इसके अलावा मैं पुलिस को हफ्ता भी देने को तैयार हूं। इतना ही नहीं, खत के अंत में लिखा गया है कि आप हमें तुरंत सूचित करें कि हमें कहां शराब का कारोबार शुरू करना चाहिए और इसके लिए हमें कितना भुगतान करना होगा?

NSUI की रिपीटर छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग

अहमदाबाद।

कोरोना महामारी के कारण गुजरात में कक्षा १०वीं और १२वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। छात्रों को मास प्रमोशन देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी तक रिपीटर छात्रों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कांग्रेस छात्रसंघ के नेताओं ने इस मामले को लेकर पीपीई किट पहनकर डीईओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं रिपीटर छात्रों को भी मास प्रमोशन देकर पास करने की मांग को लेकर एक आवेदन पत्र भी दिया गया। फिलहाल गुजरात में कक्षा १०वीं और १२वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जिसके बाद रिपीटर्स को मास प्रमोशन देने की मांग तेज हो गई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पीपीई किट पहनकर डीईओ कार्यालय के बाहर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी किया। इस मौके पर एनएसयूआई के महासचिव तौशित मकवाणा ने धमकी देते हुए कहा कि रिपीटर छात्रों की परीक्षा रद्द नहीं हुई तो निकट भविष्य में डीईओ और शिक्षा मंत्री का कड़ा विरोध किया जाएगा। गौरतलब है कि कक्षा १० में ३.६२ लाख और कक्षा १२ विज्ञान में ३२,४०० रिपीटर छात्रों की संख्या है। जबकि सामान्य स्ट्रीम में ९७ हजार छात्र परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल कक्षा १० और १२ के नियमित छात्रों का परीक्षा रद्द किया गया है।

भाजपा के कॉर्पोरेटर की अश्लील विडियो वायरल

बारडोली नपा के वार्ड नंबर एक के कॉर्पोरेटर दक्षेश शेठ का विडियो वायरल होने पर तत्काल सस्पेंड किया

सूरत।

बारडोली नगरपालिका के भाजपा के कॉर्पोरेटर दक्षेश शेठ का अश्लील विडियो वायरल होने पर फिर एक बार भाजपा की बेइज्जती हुई है। कुछ समय पहले छोटाउदेपुर में भी एक युवती ने भाजपा के बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाया था। ऐसे में भाजपा के कॉर्पोरेटर दक्षेश शेठ के विडियो कॉल पर कॉल गर्ल के सामने नग्न होकर अश्लील हरकत करता विडियो वायरल होने पर सनसनी मच गई है। दक्षेश शेठ बारडोली नगरपालिका के वार्ड नंबर एक के कॉर्पोरेटर है। विडियो वायरल होने पर तत्काल प्रभाव से पार्षद को सस्पेंड किया गया है। पार्षद के यह १ मिनट ५० सेकंड के विडियो में सबसे पहले कॉलगर्ल कपड़े उतारती है और नग्न होकर युवती अश्लील हरकतें करने लगती है। जिसके बाद होश गंवाकर पार्षद भी खुद भी कपड़े उतारकर पूरा नग्न हो जाता है और अश्लील हरकतें करने लगता है। विडियो में कॉलगर्ल अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह छिपा रही है लेकिन कॉलगर्ल को देखकर आवेश में आने पर पार्षद कैमरे में कैद हो जाता है। पार्षद के साथ का यह विडियो रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया है। बुधवार को देर शाम को यह विडियो बारडोली क्षेत्र में सोशल मीडिया में वायरल होने पर चर्चा का विषय बन गया। यह विडियो सामने आने के बाद कॉर्पोरेटर को पार्टी से सस्पेंड किया गया है। इस मामले में बताते हुए जिला भाजपा प्रमुख संदीप देसाई ने कहा कि बुधवार को उनका अश्लील विडियो वायरल होने पर पार्टी की छवि को नुकसान होने पर उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। पार्टी के सम्मान को नुकसान पहुंचाने के कृत्य को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक चर्चा ऐसी भी है कि जिनका विडियो वायरल हुआ है वह पार्षद को हनीट्रैप में फंसाने का प्रयास किया हो ऐसी संभावना है।

सुशासन बाबू के राज में धड़ल्ले से चल रहा है शराब का धंधा

सोशियल मिडया पर वायरल विडियो

सूरत भूमि, सूरत।

शहर के लिंबायत पुलिस स्टेशन में कई जगहों पर दारू के अड्डे चलाए जा रहे हैं यहां पर खुलेआम दारू का धंधा किया जा रहा है। साथ ही साथ गुजरात में लगाए गए प्लास्टिक बैन का भी अनादर किया जा रहा है क्योंकि हर दारू के अड्डे पर 100-200 किलो प्लास्टीक पड़ी रहती है। जिसकी इंक्वायरी ना हीं महानगर पालिका के कर्मचारी करते हैं और ना ही शहर की पुलिस करती है। बताया जाता है कि गुजरात राज्य में वर्षों पहले से दारूबंदी का नियम लागू किया गया है परंतु अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारत में सबसे अधिक दारू का विक्रय करने वाला राज्य गुजरात है। क्योंकि यहां की पुलिस दारू बेचने वाले को सुरक्षा देती है और दारु पीने वाले को लॉकअप में बंद करके केस बनाती है। जिससे यह साबित होता है कि गुजरात में दारू का गोरखधंधा खूब तेजी से चल रहा है और फल फूल रहा है यहां तक की गुजरात राज्य में पुलिस स्टेशनों में जितनी पुलिस है उतनी ही रिक्शे वालों की नियुक्ति की गई है। जो समय समय पर डिस्टाप के रूप में दारु पीने वाले को पकड़ने का कार्य करते हैं और रोड पर वाहन चेकिंग का भी काम कर लेते हैं। इससे पुलिस का कारोबार हल्का हो जाता है और आवक 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी की देन है कि गुजरात की पुलिस जिस पुलिस स्टेशन में मात्र 2 साल नौकरी कर लेती है उस विस्तार की हर सोसायटीओं में ब्लैक मनी के जरिए मकानों को खरीद बेच कर लेती है। जिसकी वजह से सूरत में बिल्डरों का धंधा आज भी तेजी से चल रहा है।

इसके ऊपर लॉक डाउन का भी कोई असर नहीं पड़ा साथ ही साथ महानगर पालिका के कर्मचारी प्लास्टिक बैन के नाम पर हर छोटी मोटी दुकानों में छापा मारकर वसूली कर लेते हैं जिससे मनपा की तिजोरी दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है और दारू के अड्डे पर 100 किलो से ज्यादा प्लास्टिक का बंडल पड़ा रहता है और दारू भर भर कर पाउच पड़ा रहता है वहां पर महानगरपालिका भी कभी नहीं जाती यहां तक की बताया जाता है रोज लाखों रुपए का दंड वसूलती हैं। जिससे विस्तार की जनता में त्राहिमाम का संदेश फैला हुआ है। यही है गुजरात का सुशासन जिसे पूरा भारत विकास का मॉडल मानता है शायद यही प्रक्रिया हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा पूरे भारत में सुशासन भारत का नियम लागू किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार ऐसा रुख अपना बैठी है क्या यही भारत का सही लोकतंत्र है और सही सुशासन है या सही सुरक्षा व्यवस्था है और यही स्वच्छता अभियान है देश की जनता के लिए संदेश।

AMTS-BRTS बस सेवा को तत्काल शुरू करने की मांग

गांधीनगर।

अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित एएमटीएस और बीआरटीएस बस सेवा पिछले कई माह से बंद है। जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को व्यापार और रोजगार के लिए आने-जाने के दौरान रिक्शा का सहारा लेना पड़ता है। अहमदाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव रजनी पारिख ने बस सेवा को तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू करने की मांग की है। अहमदाबाद नगर निगम के कमिश्नर से पारिख ने मांग करते हुए कहा कि कोरोना को बहाना बनाकर तुगलकी फैसला लिया जा रहा है। एएमटीएस और बीआरटीएस सेवा बंद होने की वजह से शहर के मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज भी रूअ्रस और बीआरटीएस सेवा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लाइफ लाइन के समान है। आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने काम पर जाने के लिए बस सेवा का इस्तेमाल करते हैं। अगर सरकार अन्य चीजों को खोलने का फैसला कर रही है तो फिर रूअ्रस और बीआरटीएस सेवा को बंद क्यों रखा जा रहा है। जबकि कोरोना के दैनिक मामलों में कमी दर्ज होने के बाद एसटी बस सेवा को शुरू कर दिया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले जानकारी सामने आ रही थी कि २८ मई को बस सेवा फिर से शुरू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की हरी झंडी भी मिल चुकी है। बस में यात्रियों की संख्या ५० प्रतिशत रखी जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। नगर निगम की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बस यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के यात्रियों को बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। लेकिन नगर निगम ने सेवा शुरू करने से इनकार कर दिया था।

नारोल में ९० दुकानदारों ने सील तोड़कर शुरू किया धंधा

अहमदाबाद।

अहमदाबाद नगर निगम ने शहर में बीयू परमिशन के बिना चलने वाली कई इकाईयों को सील कर दिया था। नारोल इलाके में मौजूद बिजनेस प्वाइंट बिल्डिंग के मालिक ने ९० दुकानों की सील तोड़ दी और बिना अनुमति के कारोबार शुरू कर दिया था। जिसके बाद नारोल पुलिस ने २२ कब्जाधारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। अहमदाबाद नगर निगम का एस्टेट विभाग ३१ मई को नारोल सर्किल स्थित बिजनेस प्वाइंट बिल्डिंग की ९० दुकान और ऑफिस को सील कर दिया था। नगर निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने सील तोड़ कर धंधा शुरू कर दिया था। मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम ने २२ व्यापारियों के खिलाफ नारोल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

अहमदाबाद नगर निगम की टीम ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ३०१ इकाइयों को भी सील कर दिया था। नॉर्थ वेस्ट जोन में ७७, सेंट्रल जोन में ७२, ईस्ट जोन में ६३, साउथ जोन में ५६, दक्षिण पश्चिमी जोन में १८, उत्तर जोन में ८ और पश्चिम जोन में ७ इकाइयों को सील कर दिया था। पिछले तीन दिनों में नगर निगम ने दुकानों, दफ्तर और क्लासरूम, होटल, स्कूल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बीयू परमिशन के बिना चलने वाली इन तमाम इकाईयों को सील कर दिया है। इतना ही नहीं नगर निगम की टीम आगे भी इस तरीके की कार्रवाई करने की तैयारी बना रही है।

द्वारका से और एक नकली डॉक्टर गिरफ्तार हुआ

अहमदाबाद।

कोरोना काल में जानलेवा वायरस की दूसरी लहर ने गुजरात में हाहाकार मचाया है। ऐसी स्थिति के बीच दो अलग-अलग प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के चेहरे सामने आये। एक तरफ कई लोग और डॉक्टर भी मरीजों का उपचार और सेवा में तैनात रहते देखने को मिले है।

दूसरी तरफ कई लालची लोग कोरोना के कठिन स्थिति में भी दवाइयों की कालाबाजारी और मरीजों के साथ धोखाधड़ी करके पैसे वसूलते हुए दिखाई दिए। ऐसा ही एक मामला राज्य के देवभूमि द्वारका जिले से सामने आया। जहां एक नकली डॉक्टर ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की। गुजरात में नकली डॉक्टर और बढ़ गये। रोजाना कई जिलों से नकली डॉक्टर गिरफ्तार होते है। द्वारका से भी एक नकली डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया के सलाया बंदरगाह पर से नकली डॉक्टर हुआ है। जिला एलसीबी को मिली जानकारी के आधार पर हेल्थ विभाग के अधिकारियों को साथ में रखकर छापेमारी करके और फर्जी डिग्री बिना का डॉक्टर तथा २९७ जितनी दवाइयां, मेडिकल के साधन सहित ६.३० लाख से ज्यादा का मालसामान जब्त किया गया है और कानूनी कार्रवाई की गई। द्वारका के मुख्य केंद्र खंभालिया तहसील के सलाया गांव में बाजार में स्थित मोतीयुवाल ने जनरल अस्पताल एलोपैथिक प्रैक्टिस करते डॉक्टर हमीद इब्राहीम संधार नाम का व्यक्ति प्रैक्टिस करता था। यह डिप्लोमा योग और नेचरोथेपिक की डिग्री है। लेकिन यह एलोपैथी डॉक्टर बनकर दवाई लोगों को देते होने की जानकारी जिला एलसीबी को मिली थी, जिसकी वजह से हेल्थ विभाग के अधिकारियों को साथ में रखकर छापेमारी करने पर फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर मेडिकल के साधन और दवाइयों के साथ गिरफ्तार हुआ था।

एमबीबीएस की डिग्री बिना एलोपैथिक डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करते होने से मेडिकल प्रैक्टिस से संबंधित साधन, इंजेक्शन तथा अलग-अलग एलोपैथिक की २९७ तरह की दवाइयां, सिरप, निडल और मेडिकल प्रैक्टिस के संबंधित साधनों को मिलाकर कुल ६.२८ लाख की रकम का मालसामान जब्त करके कानूनी कार्रवाई की गई है।

जूनागढ़ के पूर्व मेयर के बेटे की खुलेआम हत्या

राजकोट।

जूनागढ़ शहर के पूर्व मेयर और कांग्रेस के प्रमुख नेता लाखाभाई परमार के बेटे धर्मेश परमार की अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद हमलावर फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार धर्मेश परमार बुधवार दोपहर शहर के बिल्खा रोड पर मौजूद राम निवास के पास से एक्टिवा लेकर जा रहा था। इसी बीच उसका पहले से पीछा कर रहे अजनबियों ने अचानक धर्मेश पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और धर्मेश परमार को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने धर्मेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है।

पुलिस को इस फुटेज में तीन संदिग्ध नजर आ रहे हैं उसी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक धर्मेश परमार कांग्रेस का एक्टिव कार्यकर्ता था। जबकि उनकी पत्नी भी कांग्रेस से पार्षद रह चुकी हैं।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, सम्पादकः संजय रमाशंकर मिश्रा द्वारा ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सुरत (गुजरात) प्रिन्टर्स- भूनेश्वरा प्रिन्टर्स, प्लाट नं. 29, परमानन्द इण्डस्ट्रीयल सोसायटी, चौकसी मील के पास, उधना मगदल्ला रोड़ (गुजरात) से मुद्रित एवं ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सूरत (गुजरात) से प्रकाशित। कार्यालय फोनः 0261-2274271, (न्यायिक क्षेत्र सूरत रहेगा)